शिक्षक पोर्टल एवं नवाचार समूह
मध्यप्रदेश

एमपी बोर्ड : 3 साल के रिजल्ट से होगा 10वीं का वैल्यूएशन

पीपुल्स संवाददाता ● भोपाल
मो.नं. 9893232137

एमपी बोर्ड 10वीं एवं 12वीं के वैल्यूएशन व एग्जाम के लिए प्रस्ताव बनाकर सरकार के पास भेज दिया गया है। एक-दो दिन में आदेश जारी कर दिए जाएंगे। प्रस्ताव के मुताबिक 10वीं की परीक्षा नहीं ली जाएगी। इन्हें पिछले तीन साल के रिजल्ट के आधार पर अंक दिए जाएंगे। तीन सालों में फेल हुए छात्रों को भी 33 फीसदी अंक देकर पास कर दिया जाएगा। 12वीं की परीक्षा कोरोना संक्रमण थमने के बाद होगी। इसमें परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, यह कोरोना की परिस्थिति के अनुसार तय किया जाएगा। राज्यमंत्री इंदर सिंह परमार ने स्पष्ट कर दिया है कि 10वीं के स्टूडेंट्स को सीबीएसई की तर्ज पर जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। मार्कशीट में अंक देंगे।

पहले फेल हुए छात्रों को 33% नंबर दिए जाएंगे

12वीं की परीक्षा कोरोना संक्रमण थमने के बाद ही होगी। यदि हालात ठीक रहे तो 10वीं के प्राइवेट छात्रों के साथ इनकी परीक्षा हो सकती है।

एमपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा निरस्त कर दी गई है, लेकिन मूल्यांकन करके ही नंबर दिए जाएंगे। इसके लिए मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। 10वीं व 12वीं को लेकर 15 मई से पहले आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

–इंदर सिंह परमार,
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
स्कूल शिक्षा विभाग

सरकारी शिक्षक ने 'सांसों' के लिए 48 घंटे में जुटाए 3 लाख रुपए, पिछोर व खनियाधाना में दिए चार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर

पीपुल्स ब्यूरो • शिवपुरी
मो.नं. 7999881392

समाज में शिक्षक को भाग्य विधाता, राष्ट्र निर्माता से लेकर अज्ञानता के अंधकार को मिटाने वाले की संज्ञा दी जाती रही है। शिवपुरी जिले के पिछोर के एक छोटे से गांव करारखेड़ा निवासी सरकारी शिक्षक साकेत पुरोहित ने कोरोना संकट के बीच जब पिछोर व खनियाधाना में मरीजों के लिए ऑक्सीजन की सुचारू व्यवस्था की दरकार महसूस की तो उन्होंने इसके लिए मदद जुटाना शुरू किया। इस सकारात्मक सोच

के साथ साकेत ने क्षेत्र के लोगों की 'सांसों' के लिए सोशल साइट के जरिए अभियान शुरू किया। नतीजा यह रहा कि 48 घंटे में ही पिछोर व खनियाधाना से 2 लाख 98 हजार 620 रुपए एकत्र भी हो गए। इससे पिछोर व खनियाधाना में 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुहैया कराने के अलावा अन्य स्वास्थ्य संबंधी सामग्री खरीदी जाएगी।

शिवपुरी के मदद बैंक से मिली साकेत को प्रेरणा

साकेत बताते हैं कि उन्हें यह प्रेरणा शिवपुरी में 'मदद बैंक' के प्रमुख सेवादार बृजेश तोमर से मिली है। जिला स्तर पर तो मदद के लिए लगातार 'मदद बैंक' के हाथ आगे बढ़ ही रहे हैं। यही कारण रहा कि साकेत ने अपने अभियान को पिछोर, खनियाधाना तक ही सीमित रखा और वहीं के लोगों को जोड़कर अपील की। उनकी अपील के बाद से उनके पास लोगों के इस मुहिम में सहयोग करने के लिए लगातार मैसेज और फोन आ रहे हैं।

नेता, व्यापारी संघ से लेकर शिक्षक संघ आए आगे

साकेत की अपील के बाद हर तबके के लोग आगे आए। पिछोर की भाजपा नेत्री पूनम सोनी (बुआजी) ने 62 हजार रुपए दिए। पिछोर के व्यापारी मंडल ने 60 हजार रुपए की मदद की। राज्य शिक्षक संघ पिछोर ने भी सहयोग किया। शिक्षक साकेत का कहना है कि इस मुहिम की सफलता की खुशी तब और बढ़ गई, जब इसका असर करैरा और खोड़ के लोगों पर भी हुआ। उन्होंने भी वहां ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन के लिए राशि जुटाई है।

संक्रमित हुए शिक्षकों को इलाज के लिए मिले विशेष अवकाश सुविधा

बिना आर्डर जारी किए शिक्षकों को कोरोना ड्यूटी पर बुला रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी

रीवा ■ [illegible]

प्रदेश में अनुविभागीय अधिकारी बिना आर्डर जारी किए शिक्षकों को कोरोना ड्यूटी पर बुला रहे हैं। यह आरोप लगाते हुए समग्र शिक्षक संगठन ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है।

बताया गया कि कोरोना संक्रमण के बीच वर्तमान में प्रदेश भर में कोरोना महामारी के बचाव अभियानों में शिक्षकों को बड़ी संख्या में ड्यूटी पर लगाया गया है। जिसमें रेलवे स्टेशनों चिकित्सालय तथा जिला नगर पालिका टोल नाकों संक्रमित नागरिकों के सर्वे टीकाकरण कोविड सेंटरों सहित अनेक कोविड बचाव से संबंधित अभियानों में शिक्षकों तैनात किया गया है। जिससे बड़ी संख्या में शिक्षक संक्रमित भी हो रहे हैं। लेकिन कोरोना ड्यूटी पर कार्य करते हुए कोविड-19 से संक्रमित होने की स्थिति में राज्य शासन ने संबंधित शिक्षक- कर्मचारियों को उपचार के लिए विशेष अवकाश का कोई प्रावधान नहीं किया है। इस संबंध में समग्र शिक्षक संघ ने राज्य शासन को पत्र लिखा है। जिसमें कोविड-19 की ड्यूटी के दौरान संक्रमित हो गये शिक्षकों को उस चिकित्सकीय अवधि में उपचार के लिए 30 से 45 दिन दिवस की अवधि का विशेष अवकाश दिए जाने का प्रावधान किए जाने की मांग की है।

शिक्षकों की ड्यूटी लगाने की प्रक्रिया में भी हो सुधार

समग्र शिक्षक संघ के महामंत्री संजय तिवारी ने राज्य शासन को लिखे पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया है कि शिक्षकों की अलग-अलग स्तर पर कोरोना बचाव अभियान में सेवाएं ली भी जा रही है। लेकिन नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा आदेश प्रसारित नहीं किए जा रहे हैं। कई स्थानों पर तो शिक्षकों को मौखिक रूप से कोविड-19 से संबंधित बचाव कार्यों में लगाया जा रहा है। जिस पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। मौखिक रूप से कोरोना ड्यूटी लगाने वाले अधिकारियों पर शासन कार्यवाही करें।

बिना आर्डर के बुलाया जा रहा है शिक्षकों को

संगठन के उपाध्यक्ष नरेंद्र कुमार दुबे का कहना कि कई मामलों में नियमानुसार आर्डर जारी न किए जाने के कारण ड्यूटी के दौरान अप्रिय स्थिति निर्मित हो रही है। ऐसी स्थिति में शिक्षकों को शासन स्तर से निर्धारित सहायता मिलने में समस्या आ रही है। वहीं निर्धारित आदेश के बिना कोरोना ड्यूटी करने वाले शिक्षक अर्जित अवकाश की पात्रता से भी वंचित हो रहे हैं। उन्होंने राज्य शासन के समक्ष यह भी मांग उठाई कि प्रदेश भर में कोरोना ड्यूटी में लगे शिक्षकों को ड्यूटी के एवज में अर्जित अवकाश दिया जाए।

डीपीआई ने सभी जिलों से पूछा कितने अध्यापकों की मौत हुई

अंतिम भुगतान और एन्युटी की कार्रवाई के निर्देश

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

लोक शिक्षण संचालनालय ने कोरोना संकमण काल में अध्यापकों की मृत्यु के बाद अंतिम भुगतान एवं एन्युटी की कार्रवाई और जानकारी मुख्यालय भेजने को लेकर जिलों को आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि निदेशों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित करें, इसमें कोई लापरवाही नहीं बरतें। अन्यथा इसका पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी का होगा। लोक शिक्षण आयुक्त जयश्री कियावत ने प्रदेश भर के जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी करते हुए कहा है कि जिला अंतर्गत ऐसे कितने अध्यापक हैं, जिनकी कोरोना महामारी या अन्य कारणों से मृत्यु हुई है।

यह होगी कार्रवाई

आदेश में कहा गया है कि ऐसे अध्यापक जिनका नवीन शैक्षणिक संवर्ग में उच्चतर माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक पर नियुक्ति हो चुकी है तथा उन्हें एम्प्लाई आईडी आवंटित की जा चुकी है तथा उनके वेतन का भुगतान आईएफएमआईएस प्रणाली के तहत किया जा रहा है, उनको कोषालय के माध्यम से अंतिम भुगतान किया जाएगा। साथ ही ऐसे नवीन शैक्षणिक संवर्ग के अध्यापक जिनकी नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन उन्हें एम्प्लाई कोड आवंटित नहीं हुआ है, ऐसे अध्यापकों के अंतिम भुगतान की कार्रवाई पैरा 1 के अनुसार किया जाना सुनिश्चत करें। इस कार्रवाई से संचालनालय को अवगत कराएं।

दैनिक भास्कर भोपाल 13-05-2021

लोक शिक्षण आयुक्त का आदेश

मृत अध्यापकों के परिजनों को तत्काल करें सभी भुगतान

भोपाल| कोरोना काल में मृत अध्यापकों के परिजनों को इन अध्यापकों के खातों में जमा राशि एवं पेंशन का भुगतान तत्काल किया जाए। यह आदेश आयुक्त लोक शिक्षण जयश्री कियावत बुधवार को सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी किए हैं। आयुक्त ने आदेश में कहा है कि इन अध्यापकों के नॉमिनी से सभी दस्तावेज लेकर राशि और पेंशन का भुगतान करें। एक आदेश मंगलवार को भी जारी किया गया था। इसमें शिक्षक संवर्ग की तरह अध्यापक संवर्ग को भी सामूहिक बीमा योजना का लाभ देने का जिक्र था। आयुक्त ने मंगलवार को जारी आदेश में कहा है कि 1 जुलाई 2018 से नए कैडर में शामिल हुए अध्यापकों को सामूहिक बीमा योजना का लाभ दिया जाए। इस योजना के तहत प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों को ढाई लाख रुपए एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों को पांच लाख रुपए का फायदा होगा।

वहीं, दूसरी ओर शिक्षक कांग्रेस के प्रांतीय प्रवक्ता सुभाष सक्सेना, अध्यापक संगठन के संयोजक उपेंद्र कौशल, आजाद अध्यापक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष शिवराज वर्मा सहित अन्य संगठनों के पदाधिकारियों का कहना है कि यह सुविधाएं तो पहले से मिल रही है। इसमें नया कुछ भी नहीं है।

कोरोना से मृत शिक्षकों का अंतिम भुगतान तत्काल करें

डीपीआई ने जिलों से मंगाई मौतों की जानकारी

पीपुल्स संवाददाता ● भोपाल

मो.नं. 9893231237

लोक शिक्षण संचालनालय ने कोरोना संकमण काल में अध्यापकों की मौत के बाद अंतिम भुगतान एवं एन्युटी की कारवाई और जानकारी मुख्यालय भेजने को लेकर जिलों को आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि निर्देशों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित करें, इसमें कोई लापरवाही नहीं बरते। अन्यथा इसका पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी का होगा। लोक शिक्षण आयुक्त जयश्री कियावत ने प्रदेश भर के जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी करते हुए कहा है कि जिला अंतर्गत ऐसे कितने अध्यापक हैं जिनकी कोरोना महामारी या अन्य कारणों से मृत्यु हुई है, इनके नामिनी से सभी दस्तावेजों को प्राप्त करते हुए अध्यापकों के प्रान खाते में जमा राशि के अंतिम भुगतान तथा नामिनी से एन्युटी परचेस की जानकारी प्राप्त कर तत्काल नियमानुसार कार्यवाही की जाए, ताकि इन्हें शीघ्र पेंशन प्राप्त हो सके। डीपीआई ने कहा है कि ऐसे अध्यापक जिनका नवीन शैक्षणिक संवर्ग में उच्चतर माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक पर नियुक्ति हो चुकी है तथा उन्हें एम्प्लाई आई डी आवंटित की जा चुकी है तथा उनके वेतन का भुगतान आईएफएमआईएस प्रणाली के तहत किया जा रहा है।

डीपीआई ने जिलों से पूछा, कोरोना संक्रमण से कितने शिक्षकों की हुई मौत

शिक्षक संगठन 5 सौ से अधिक शिक्षकों की मौत का कर रहे दावा

भोपाल (शाप्र)। लोक शिक्षण संचालनालय ने कोरोना संक्रमण काल में जिलों से शिक्षकों की मौत की जानकारी मांगी है। जिससे अध्यापकों की मृत्यु के अंतिम भुगतान एवं एन्युटी की कार्रवाई त्वरित की जा सके। साथ ही अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि निर्देशों का पालन कड़ाई से नहीं करने पर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी उत्तरदायी होंगे। दूसरी तरफ शिक्षक संगठनों का दावा है कि पांच सौ से अधिक शिक्षकों की मौत हो चुकी है। आयुक्त लोक शिक्षण जयश्री कियावत ने प्रदेश भर के जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी करते हुए कहा है कि जिला अंतर्गत ऐसे कितने अध्यापक हैं जिनकी कोरोना महामारी या अन्य कारणों से मृत्यु हुई है। इनके नामिनि से सभी दस्तावेजों को प्राप्त करते हुए अध्यापकों के प्रान खाते में जमा राशि के अंतिम भुगतान तथा नामिनि से एन्युटी परचेस की जानकारी प्राप्त कर तत्काल नियमानुसार कार्यवाही की जाए, ताकि इन्हें शीघ्र पेंशन प्राप्त हो सके। आदेश में कहा गया है कि ऐसे अध्यापक जिनका नवीन शैक्षणिक संवर्ग में उच्चतर माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक पर नियुक्ति हो चुकी है तथा उन्हे एम्प्लाई आईडी आवंटित की जा चुकी है तथा उनके वेतन का भुगतान आईएफएमआईएस प्रणाली के तहत किया जा रहा है, उनको कोषालय के माध्यम अंतिम भुगतान किया जाएगा। साथ ही ऐसे नवीन शैक्षणिक संवर्ग के अध्यापक जिनकी नियुक्ति हो चुकी है लेकिन उन्हे एम्प्लाई कोड आवंटित नहीं हुआ है ऐसे अध्यापकों के अंतिम भुगतान की कार्यवाही पैरा 1 के अनुसार किया जाना सुनिश्चत करें।

12वीं के 6 हजार छात्रों की परेशानियों को दूर कर रहे 95 सब्जेक्ट एक्सपर्ट

छात्रों को सब्जेक्ट एक्सपर्ट के वॉट्सएप नंबर दिए गए हैं

ग्वालियर। जिले के गवर्मेंट स्कूलों में कक्षा 12वीं में 6 हजार छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। छात्र घर पर ही ऑनलाइन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। शिक्षा विभाग ने छात्रों को पढ़ाई के दौरान आने वाली विषय से संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए 15 विषयों के 95 सब्जेक्ट एक्सपर्टों का पैनल बनाया है। यह सब्जेक्ट एक्सपर्ट छात्रों की गणित, भौतिकी, रसायनशास्त्र व अन्य विषय से संबंधित हर परेशानी का समाधान कर रहे हैं, ताकि 12वीं का रिजल्ट अच्छा रहे।

जिले के शिक्षा विभाग ने छात्रों को विशेष विशेषज्ञों के वॉट्एसएप मोबाइल नंबर उपलब्ध करा दिए हैं। छात्र वॉट्सएप के जरिए ही प्रॉब्लम शेयर करके उनका सोल्यूशन पूछ रहे हैं। सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी छात्रों की प्रॉब्लम को दूर कर रहे हैं। डीईओ विकास जोशी, एडीपीसी अशोक दीक्षित व अन्य अधिकारी छात्रों से फीडबैक भी ले रहे हैं कि उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन किया जा रहा है या नहीं? छात्रों से यही जवाब मिल रहे हैं कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट हर संभव मदद कर रहे हैं।

> जिले के गवर्मेंट स्कूलों में कक्षा 12वीं के 6 हजार छात्रों की विषय से संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए 95 विषय विशेषज्ञों का पैनल बनाया गया है। छात्रों को विशेषज्ञों के वॉट्सएप नंबर दिए गए हैं, छात्र वॉट्सएप पर ही प्रश्न पूछते हैं और एक्सपर्ट द्वारा सका जवाब दिया जाता है।
>
> **अशोक दीक्षित,** एडीपीसी

सीबीएसई स्कूलों में इस सत्र में सिर्फ 20 फीसद एडमिशन

भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। कोरोना संक्रमण के कारण स्कूल बंद हैं। ऐसे में पिछले सत्र में अधिकांश स्कूलों में एडमिशन कम हुए थे। इस बार भी स्कूलों में वही स्थिति है। राजधानी के सीबीएसई स्कूलों में जनवरी से एडमिशन प्रक्रिया शुरू करने के कारण 15 से 20 फीसद एडमिशन ही हुए हैं, लेकिन एमपी बोर्ड के निजी व सरकारी स्कूलों में तो एडमिशन प्रक्रिया शुरू भी नहीं हो सकी है।

सीबीएसई स्कूलों में जनवरी से नए सत्र के एडमिशन शुरू हो जाते हैं। इसके चलते राजधानी के सहोदय ग्रुप के सभी स्कूलों में जनवरी और फरवरी में15 से 20 फीसद बच्चों ने एडमिशन ले लिया है। इसके बाद कोरोना संक्रमण बढ़ा और स्कूल बंद होने के साथ ही एडमिशन प्रक्रिया रोक दी गई है। इन स्कूलों ने पिछले वर्ष मार्च तक अपने एडमिशन पूरे

कर लिए थे। दूसरी ओर कोरोना के कारण सालभर स्कूल व अभिभावकों के बीच फीस की लड़ाई चलती रही और कोर्ट व सरकार ने केवल शिक्षण शुल्क लेने के आदेश दिए थे। इस कारण भी एडमिशन नहीं हुए। कम एडमिशन होने पर अन एडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने जताई चिंता है।

स्कूलों में जनवरी से एडमिशन प्रक्रिया शुरू की गई थी। कोरोना संक्रमण बढ़ने पर प्रक्रिया धीमी चली और 20 फीसद ही एडमिशन हो पाए।

-विनीराज मोदी, अन एडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन

परीक्षा की तैयारी में जरूरी है लिखने का अभ्यास करना

जबलपुर (नईदुनिया रिपोर्टर)। कोविड के कारण पूरा साल विद्यार्थियों ने आनलाइन पढ़ाई की। इस पढ़ाई में शिक्षकों ने आनलाइन ही विषय को समझाया और विद्यार्थियों ने आनलाइन ही बातों को समझा। इस प्रक्रिया में बच्चों का लिखने का अभ्यास पूरी तरह छूट गया है। जबकि जो परीक्षा होती है उसमें तीन घंटों तक विद्यार्थी को सिर्फ लिखना ही होता है। बाकी सारी कक्षाओं की परीक्षा तो हो चुकीं हैं। दसवीं के बच्चों को असिसमेन्ट के आधार पर आगे बढ़ाया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान हैं 12वीं कक्षा के विद्यार्थी। जिन्हें अभी तक पता नहीं है कि परीक्षाएं होना भी हैं या नहीं। होंगी भी तो कब होंगी। इस असमंजस की स्थिति के बीच बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। और साथ ही लिखने का अभ्यास भी।

काउंसलर वर्षा चौहान ने बताया कि आनलाइन पढ़ाई से बच्चों का बहुत नुकसान हुआ है। एक विद्यार्थी के रूप में जो आदतें होना थीं वो छूट गई है। इस समय जो परीक्षा की तैयारी चल भी रहीं हैं उनमें विद्यार्थी पढ़- पढ़ कर थक चुके हैं। तो अब पढ़ाई के तरीके में थोड़ा बदलाव करते हुए लिखने का अभ्यास करें। न सिर्फ लिखने का बल्कि लगातार तीन घंटे टेबल- कुर्सी पर बैठ कर लिखने का

आनलाइन पढ़ाई होने पर विद्यार्थियों की छूट गई लिखने की आदत

अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि इस समय लिखने की आदत छूटी होने से बच्चों को परीक्षा देने में लगातार बैठने और लिखने में ही सबसे ज्यादा परेशानी होगी। वैसे भी कहा जाता है कि परीक्षा लिखने की होती है। जिसने जितना अच्छा पेपर लिखा नंबर उसी के आधार पर मिलते हैं। अब जब सारी जानकारी होने पर भी बच्चे परीक्षा में लिख भी नहीं पाएंगे तो फिर पढ़ाई का क्या अर्थ। इसलिए अब समय है कि बच्चे लिख कर रिवीजन करें। तभी इस समय का सदुपयोग हो सकेगा और परीक्षा में इसका लाभ भी मिलेगा। विद्यार्थी प्राची ठाकुर ने बताया कि वे हर दिन एक घंटा लिखने का अभ्यास कर रही हैं। जिससे परीक्षा में परेशानी न हो। और लिख कर पढ़ने से पढ़ा हुआ ज्यादा समय तक याद भी रहता है।

शहर कांग्रेस कमेटी ने ज्ञापन सौंपकर की मांग

6 माह के लिए बिजली बिल और स्कूल फीस हो माफ

विदिशा। प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपते कांग्रेसजन।

जागरण विदिशा

शहर कांग्रेस कमेटी ने बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि कोरोना महामारी में लॉकडाउन के चलते रोजगार पूरी तरह से ठप्प हो जाने के कारण आमजन आर्थिक रूप से परेशान है। ऐसी विकट स्थिति में आमजनों के जलकर, संपत्ति कर एवं घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल 6 माह के लिए माफ किए जाएं ताकि कोविड से जूझते नागरिकों को संबल मिल सके साथ ही स्कूल फीस भी माफ करने की मांग की। साथ ही कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र राठौर ने कहा कि मई में सीएमओ 25 वार्डों के हर घर को सैनेटाइज करने का झूठा दावा किया गया है। जिसकी जांच की जाना चाहिए एवं सैनेटाइजर का सोशल ऑडिट कराने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने वालों में अरूण अवस्थी, राजकुमार पासी, खलील गौरी आदि कांग्रेस नेता मौजूद रहे।

शिक्षक कर रहे हैं जनसेवा के कार्य

बेसहारा, गरीबों को भोजन कराने के साथ ही मवेशियों के लिए किया भूसे का इंतजाम

पीपुल्स संवाददाता ● इछावर
मो.नं. 9340684657

भूखों को भोजन कराना ही सबसे बड़ा पुण्य का काम है। इस भावना के साथ नगर के एक सेवानिवृत्त शिक्षक कोरोना की इस महामारी में रोजी-रोटी के संकट से जूझ रहे गरीब और बेसहारा लोगों को भोजन की व्यवस्था कराने के साथ ही मवेशियों के लिए भूसे का भी इंतजाम कर रहे हैं।

नगर के सेवानिवृत्त शिक्षक शैलेंद्र कुमार गुप्ता सैकड़ों बेसहारा लोगों ओर भूख से व्याकुल मवेशियों के लिए देवदूत बने हुए हैं। दरअसल वह जरुरतमंदों को भोजन की व्यवस्था कराने के साथ ही गौशालाओं में मौजूद मवेशियों के लिए भूसे का इंतजाम भी कर रहे हैं। इछावर नगर के वर्मा चौक में रहने वाले शैलेंद्र कुमार गुप्ता कुछ साल पहले शिक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। सेवा से निवृत्त होने के बाद से ही वह समाज सेवा के कार्यों में लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। लोगों के लिए भोजन की वयवस्था करने के अलावा वह मवेशियों के लिए भूसे का भी इंतजाम कर रहे हैं। इस रसोई में गुप्ता द्वारा भी सहयोग किया गया है। रामरसोई का संचालन पिछले 26 दिनों से लगातार किया जा रहा है। इसमें सौरभ मकरैया, शुभम मकरैया, प्रशांत शर्मा, बिट्टू सोनी, दिनेश मेवाड़ा आदि का विशेष योगदान है।

अध्यापकों से छलावा बंद करे सरकार

कर्मचारी संघ ने की पुरानी पेंशन नीति लागू करने की मांग

पीपुल्स संवाददाता ● जबलपुर

editor@peoplessamachar.co.in

अध्यापकों तथा नवीन अंशदायी पेंशन योजना (एन.पी.एस.) के अंतर्गत आने वाले प्रदेश के लगभग 5 लाख से अधिक कर्मचारियों को शासन के अंशदान को 10 प्रतिशत से बढ़ा कर 14 प्रतिशत किया गया है।

इस संबंध में मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ अध्यापक प्रकोष्ठ ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा अपने नवीन अंशदायी पेंशन योजना के कर्मचारियों को 14 प्रतिशत का अंशदान कई वर्ष पूर्व से ही दिया जा रहा है। वहीं प्रदेश सरकार 4 प्रतिशत अंशदन बढ़ोत्तरी का झुनझुना पकड़ा कर पुरानी पेंशन योजना स्वीकृत करने से बचने का कार्य किया है । इससे कर्मचारियों में भारी आकोश व्याप्त है।

ये लगाया आरोप

संघ ने कहा विधायकों, सांसदों को पुरानी पेंशन के तहत लाभ प्रदान किये जा रहे हैं। जबकि 35 से 40 वर्ष शासकीय कार्य निष्ठा व ईमानदारी से करने वाले लोक सेवकों से यह दोहरा मापदण्ड अपनाया जा रहा है। संघ के मुकेश सिंह, आलोक अग्निहोत्री, सुनील राय, अजय सिंह ठाकुर, तरूण पंचौली, मनीष चौबे, नितिन अग्रवाल, गगन चौबे, श्यामनारायण तिवारी, प्रणव साहू, राकेश उपाध्याय, मनोज सेन, राकेश दुबे, गणेश उपाध्याय, धीरेन्द्र सोनी, मो. तारिक, प्रियांशु शुक्ला, मनीष लोहिया, सुदेश पाण्डेय, मनीष शुक्ला, राकेश पाण्डेय विनय नामदेव, देवदत्त शुक्ला, सोनल दुबे, ब्रजेश गोस्वामी, विजय कोष्टी, अब्दुल्ला चिस्ती, पवन ताम्रकार, संजय श्रीवास्तव, आदित्य दीक्षित, संतोष कावेरिया, जय प्रकाश गुप्ता, आनंद रैकवार, वीरेन्द्र धुर्वे, मनोज पाठकर, सतीश पटेल ने मांग की है कि पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए।

पीपुल्स पब्लिक स्कूल के छात्रों ने मां के साथ भेजे फोटोज

मां अच्छी शिक्षिका के रूप में हमें सही राह दिखाती है: रश्मि बी कपूर

रिपोर्टर • IamBhopal
Mobile no. 9582826011

'जब कागज पर लिखा, मैंने मां का नाम कलम अदब से बोल उठी हो गए चारों धाम' पीपुल्स पब्लिक स्कूल में मदर्स डे सेलिब्रेशन हुआ। इसका उद्देश्य विश्व की सभी माताओं को सम्मान देना है। मदर्स डे साल का खास दिन होता है। जो भारत की सभी माताओं को समर्पित होता है ' मां ईश्वर का दिया गया सबसे सुंदर व अमूल्य उपहार है। बच्चे को जन्म देने से लेकर उसे देश का श्रेष्ठ नागरिक बनाने में मां की अहम भूमिका होती है। स्कूल के प्री प्राइमरी व प्राइमरी विंग के बच्चों ने अपनी अपनी मम्मी के साथ सुंदर फोटो भेजें। फोटो के साथ ही उन्होंने स्लोगन भी प्रस्तुत किए। हमारे सेकेंडरी के स्टूडेंट्स द्वारा ग्रीटिंग कार्ड बनाए गए ,कार्ड के साथ ही उन्होंने अपनी मां को संबोधित करते हुए मैसेज प्रस्तुत किए। इस अवसर पर स्कूल की प्रिंसिपल रश्मि बी कपूर ने कहा कि दुनिया में मां ही एकमात्र ऐसी हस्ती है जो आपको आपके जन्म से पहले ही प्यार करने लगती है इसलिए वह ईश्वर के समान पूजनीय है। इस दिन हम प्रत्येक मां को नमन करते हैं, क्योंकि देश का श्रेष्ठ व भावी , नागरिक मां बनाती हैं। मां के रूप में हमारी देखभाल, अच्छी शिक्षिका के रूप में हमें सही और गलत की पहचान कराती है।

भास्कर

संक्रमित शिक्षक की किल करोना सर्वे में लगाई ड्यूटी

भास्कर संवाददाता | शिवपुरी

शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों की किल कोरोना सर्वे के लिए ड्यूटी बिना देखे परखे लगाई जा रही है। न तो ड्यूटी लगाने वाले को यह पता कि कौन-सा शिक्षक कोरोना पॉजिटिव है, घर में उसके क्या हालात हैं और न ही उनके बारे में कोई डाटाबेस तैयार किया गया। हालात यह हैं कि जो शिक्षक कोरोना संक्रमित है उनकी भी किल कोरोना सर्वे में ड्यूटी लगा दी गई है। यह प्रशासनिक अधिकारियों की गड़बड़ी है और उन्हें इसमें सुधार करना चाहिए।यह मांग राज्य कर्मचारी संगठन के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह रघुवंशी और उनके साथियों ने जिला प्रशासन से की है।

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि शिक्षा विभाग के जिले के सभी कर्मचारियों की किल कोरोना अभियान में ड्यूटी अंधाधुंध लगाई जा रही है।अधिकारी यह भी नहीं देख रहे हैं कि किस शिक्षक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है या फिर कोई स्वर्गवासी हो गया है। कोई हॉस्पिटल में भर्ती है या घर पर क्वॉरेंटाइन है। इस तरह के आदेश खनियांधाना और नरवर में ड्यूटी के लिए जारी हुए है। उन्होंने कलेक्टर साहब से आग्रह है कि कृपया ऐसे आदेश पर रोक लगाएं, जो लोग कोरोना पॉजिटिव नहीं है उनकी ड्यूटी जहां भी चाहें लगाएं पर पॉजिटिव लोगों को तो बख्श दिया जाए।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में प्रवेश-साक्षात्कार

अनुबंधात्मक आधार पर पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति

भारत सरकार के यूओ नं. O.IV-3/2020-Pers.II दिनांक 93/05/2021, सेवानिवृत्त सीएपीएफ कर्मियों से सीएपीएफ एवं आसाम राईफल में पैरामेडिकल कैडर में रिक्तियों की पूर्ति हेतु चयन प्रक्रिया संचालित करने हेतु सीआरपीएफ को कार्य नोडल बल घोषित किया गया है।

2. 60 वर्ष से अधिक आयु के सेवानिवृत्त कर्मियों को पैरामेडिकल ड्यूटीज हेतु ***एक वर्ष की अवधि के लिये*** 62 वर्ष की आयु तक नियुक्त किया जायेगा।

3. ऐसे नियुक्त कर्मियों की नियुक्ति एवं वेतनमान डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स ओएम नं. 3-25/2020-EIIIA दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के अनुसार निर्धारित होगी। सेवानिवृत्त केंद्र शासन कर्मचारियों की अनुबंध नियुक्ति के मामले में निर्धारित वेतनमान जो भी अंतिम वेतन प्राप्त हुआ हो ऋण पेंशन योग ट्रांसपोर्ट एलाउंस, सेवानिवृत्ति के समय में नियुक्ति को लागू दर से अधिक नहीं जिस पर डीए लागू नहीं होगा।

4. सीएपीएफ की रिक्तियाँ निम्न के अंतर्गत हैं :-

एआर		बीएसएफ		सीआरपीएफ		आईटीबीपी		एसएसबी	
रैंक	रिक्ति	रैंक	रिक्ति	रैंक	रिक्ति	रैंक	रिक्ति	रैंक	रिक्ति
सिस्टर	01	एसआई/स्टाफ नर्स	49	स्टाफ नर्स	231	स्टाफ नर्स	18	एसएम (सिस्टर आई/सी)	1
नायब सूबेदार/ स्टाफ नर्स	52	एएसआई/लैब टेक	40	रेडियोग्राफर	17	मेडीक्स	67	इंस्पे (सिस्टर आई/सी)	3
वारंट ऑफिसर फॉर्मासिस्ट	26	एचसी (जू.) एक्स-रे असिस्टेंट	41	फिजियोथेरेपिस्ट	100	फार्मासिस्ट	11	एसआई (स्टाफ नर्स)	39
राईफलमैन लैब असिस्टेंट	11	एच सी फिजियोथेरेपी असिस्टेंट	44	फार्मासिस्ट	123	लैब टेक	01	एसआई (फार्मासिस्ट)	1
राईफलमैन नर्सिंग असिस्टेंट	46	कांस्टेबल (एनए)	192	डाईटीशियन	01	एएनएम	15	एएसआई (फार्मासिस्ट)	19
आरएफडब्ल्यू फीमेल असिस्टेंट	08			ब्लड बैंक टेक	01	रेडियोग्राफर	01	एसआई (रेडियोग्राफर)	1
आरएफडब्ल्यू आया	05			लैब टेक्नीशियन	110			एएसआई (रेडियोग्राफर)	9
आरएफडब्ल्यू फीमेल सफाई	07			ईसीजी टेक्नीशियन	01			एएसआई (लैब टेक)	12
				डेंटल टेक्नीशियन	05			एएसआई (ओटी)	2
				डब्ल्यूबी/एनए	590			एएसआई (डेंटल टेक)	2
				एक्स-रे टेक्नीशियन	93			एचसी (नर्सिंग असिस्टेंट)	8
				इलेक्ट्रीशियन	01			एचसी (स्टीवार्ड)	2
				डायलीसिस टेक्नीशियन	08			सीटी (आया)	5
				सीटी/ किचन सर्विस	125			सीटी (लैब असिस्टेंट)	23
				सीटी/डब्ल्यूएम	04			एचसी (फिजियोथेरेपी)	15
				सीटी/एसके	128			एचसी (एक्स-रे असिस्टेंट)	15
								सीटी (एनए/मेडिक)	47
								एएसआई (मेडिक)	29
								एएसआई (एक्स-रे-टेक)	1
								एचसी (मेडिक)	02
								हॉस्पीटल कुक	6
								प्यून	9

ए) अवधि समाप्त हो जाने पर अनुबंध स्वतः समाप्त हो जायेगा। यद्यपि, नियुक्ति (दोनों ओर से) एक माह का नोटिस प्रदान कर या एक माह के नोटिस का भुगतान कर या एक माह के वेतन का भुगतान कर बिना कोई कारण बताये या सक्षम प्राधिकारी को तीन माह की सेवा में संतुष्ट करने में असफल होने पर बर्खास्त की जा सकती है।

बी) नियुक्त व्यक्ति किसी भी लाभ जैसे प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेच्युटी, मेडीकल अटेंडेंस ट्रीटमेंट, सीनियरिटी, प्रमोशन आदि या नियमित आधार पर नियुक्त शासकीय सेवक को उपलब्ध अन्य लाभ की पात्र नहीं होगा। नियुक्त व्यक्ति, सीआरपीएफ के अंतर्गत किसी पोस्ट में नियमित नियुक्ति के दावे या अधिकार का पात्र नहीं होगा।

सी) नियुक्त व्यक्ति की कार्यावधि सीआरपीएफ अस्पतालों/स्थापनाओं के शेड्यूल के अनुसार अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय की जायेगी।

डी) नियुक्ति, देश के किसी भाग में सेवा करने के दायित्व से युक्त है। यद्यपि, चयन के पश्चात् स्थान की प्राथमिकता मान्य होगी।

ई) नियुक्त व्यक्ति उनको दिए कर्तव्य को पूर्ण करेगा/करेगी। सक्षम अधिकारी, उसे कोई भी कर्तव्य प्रदान करने के अधिकारी है, जैसा भी और जब भी आवश्यक हो। ऐसे कार्य का अतिरिक्त/अधिक भत्ता लागू नहीं होगा।

एफ) नियुक्त व्यक्ति की अवकाश पात्रता डीओपी एंड टी ओ. एम नं. 12016/3/84-एस्टेट(एल) दिनांक 12 अप्रैल 1985, ओ. एम नं. 12016/1/90-एस्टेट(एल) दिनांक 05 जुलाई 1990 एवं ओ. एम नं. 12016/2/99-एस्टेट(एल) दिनांक 12 जुलाई 1999 एवं समय समय पर संशोधित के अनुसार शासित होगी।

जी) अनुबंधात्मक आधार / भर्ती आधार पर सीआरपीएफ नियुक्ति की अवधि दौरान टीए/डीए का भुगतान नहीं किया जायेगा।

एच) अनुबंध की अवधि के दौरान वह बल के अनुशासन के मानकों के अनुपालन के विधाधीन होगा/होगी एवं प्रशासकीय अधिकारी के आदेशों का पालन करेगा/करेगी, चाहे वह लिखित हो या मौखिक।

आई) नियुक्ति के लिये लागू नियम व शर्तों के लिये इच्छुक पूर्व कर्मचारी आवेदक वेबसाईट www.crpf.nic.in रेफर कर सकते हैं।

जे) कार्यग्रहण के समय चिकित्सीय परीक्षण आयोजित होगा।

5) इच्छुक पूर्व-कर्मचारियों से निवेदन है कि उनका लिखित आवेदन डीआईजी रिक्रूटमेंट सीआरपीएफ को ई-मेल आईडी : digrect@crpf.gov.in पर इस विज्ञापन के प्रकाशन के तीन दिवस के भीतर करें।

6) आगामी दिशानिर्देशों का समय-समय पर वेबसाईट www.crpf.gov.in पर अनुगमन किया जा सकता है।

davp 19140/11/0026/2122

डीआईजी (रिक्रूटमेंट) डीटीई

दैनिक भास्कर
भोपाल 13-05-2021

पश्चिम मध्य रेल

कार्यालय मंडल रेल प्रबन्धक, कार्मिक शाखा, भोपाल

पत्र सं.:- पमरे/का.भो./विज्ञप्ति/कोविड-19/सीएमपी/राज. दिनांक: 12/05/2021

विज्ञप्ति

प.म.रे. के भोपाल मंडल में संविदा आधार पर विशेषज्ञ चिकित्सको की नियुक्ति

विषयः-पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल पर कोविड-19 की महामारी के कारण विशेषज्ञ चिकित्सक को पूर्णकालिक संविदा आधार पर दिनांक 31/03/2022 अथवा कोविड-19 महामारी समाप्त होने तक जो भी पहले हो तक नियुक्ति संबंधित।

रेलवे बोर्ड के विद्यमान निर्देशों के अनुसार कोविड-19 वैश्विक महामारी से संबंधित चिकित्सीय समस्याओं के निराकरण को दृष्टिगत रखते हुए पश्चिम मध्य रेल के भोपाल मंडल में संविदा आधार पर पूर्णकालिक विशेषज्ञ चिकित्सक के पदो को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते है। शासकीय सेवा-निवृत चिकित्सक (रेलवे/राज्य/केन्द्रीय) भी नियुक्ति हेतु पात्र है। पदो का विवरण निम्नानुसार है:-

चिकित्सालयः भोपाल मंडल के विभिन्न चिकित्सालयों हेतु। **पद का नामः** विशेषज्ञ चिकित्सक- (1) जनरल फीजिशियन (General Physician & MD Medicine) (2) चेस्ट फीजिशियन (Chest Physician) (3) एनेस्थेसियोलोजिस्ट (Anesthesiologist) **पदों की संख्याः** 12 **शैक्षणिक योग्यताः** संबंधित विषय में स्नातकोत्तर (पी.जी.) उत्तीर्ण।

इच्छुक पात्र अभ्यार्थी अपने विवरण संलग्न प्रॉफार्मा में भरकर उसके साथ प्रमाण-पत्र पी.डी.एफ में ईमेल आईडी srdpobpl@gmail.com पर प्रत्येक रविवार प्रातः 11.00 बजे तक अपलोड कर सकते हैं। प्रत्येक रविवार तक आवेदन अपलोड करने वाले अभ्यार्थियों की उपयुक्तता जांचने हेतु साक्षात्कार वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से लिंक https://meet.google.com/kpr-hxyh-bjh पर प्रत्येक सोमवार को प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक आयोजित किया जाएगा। संविदा आधार पर चिकित्सकों के उपरोक्त दर्शाए गए पदों के बराबर पैनल बनाया जाएगा परिस्थितियों की आवश्यकतानुसार उसमें से चिकित्सकों को मेरिट के आधार पर संविदा नियुक्ति प्रदान की जाएगी। पारिश्रमिकः संविदा आधार पर नियुक्त पूर्णकालिक विशेषज्ञ चिकित्सक हेतु मासिक पारिश्रमिक रूपये 95000/- (मकान किराया भत्ता एवं परिवहन भत्ते सहित) रहेगा। संविदा नियुक्ति संविदा आधार पर रेलवे/शासकीय सेवा से सेवानिवृत चिकित्सक हेतु पूर्णकालिक संविदा चिकित्सक के पद पर नियुक्ति उपरांत सेवा निवृति पर उन्हें मिलने वाली पेंशन एवं मासिक पारिश्रमिक का योग उनके अंतिम वेतन से अधिक नही होगा। अन्य शर्तें :- (1) संविदा आधार पर नियुक्ति हेतु अधिसूचना जारी होने की तिथि को अभ्यार्थी की अधिकतम आयु 53 वर्ष से अधिक न हो। (2) सेवा निवृत रेलवे/अन्य शासकीय चिकित्सको की CMP के तौर पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 65 वर्ष से अधिक न हो। अभ्यार्थियों को सभी प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति नियुक्ति के समय प्रस्तुत करना होगी।

कृते मरिप्र (कार्मिक) भोपाल

444/2021

खान-पान से संबंधित शिकायत हेतु टोल फ्री नम्बर 1800111321 पर सम्पर्क करें।

ओपन बुक परीक्षा का फार्म भरने 30 मई तक का वक्त, यूनिवर्सिटी की तैयारी नहीं

जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी में जून से आयोजित परीक्षाओं के लिए आवेदन करने की तिथि 30 मई तय हुई है। उच्च शिक्षा विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। कई यूनिवर्सिटी ने इसके बाद परीक्षा के आदेश भी जारी कर दिए हैं, लेकिन रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी से इस मामले को लेकर तस्वीर साफ नहीं हुई है। अधिकारी मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं विद्यार्थी अपने सत्र को समय पर पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। ज्ञात हो कि उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के निर्देश पर 30 मई तक सभी स्नातक और स्नातकोत्तर

परीक्षाओं के परीक्षा फार्म भरवाने की व्यवस्था दी है। यूनिवर्सिटी को इस संबंध में लिंक खोलनी है ताकि जून से परीक्षा प्रारंभ हो सके। इस बार कोरोना महामारी में ओपन बुक एग्जाम होना है। अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को भी इसी तरह से परीक्षा में शामिल किया जाना है लेकिन अभी तक इसकी कोई कार्य योजना नहीं तय हो पाई है। विभाग ने शजारीरिक दूरी के साथ ज्यादा से ज्यादा केंद्रों में परीक्षा कापियों का संग्रह करने की व्यवस्था करने को कहा है।

लाकडाउन से हो रही देरी : कुलसचिव प्रो. एनसी पेंडसे ने कहा कि लाकडाउन की वजह से प्रशासन कोई निर्णय नहीं कर रहा है। परीक्षा आवेदन भरवाने के लिए कियोस्क खुलना चाहिए। लाकडाउन में एमपी आलनाइन के सारे कियोस्क बंद हैं। ऐसे में विद्यार्थियों को परेशानी होगी। वहीं अन्य यूनिवर्सिटी ने विद्यार्थियों को मोबाइल, कम्प्यूटर के जरिए घर बैठे ही परीक्षा आवेदन भरने के लिए कहा है ताकि कोरोना संक्रमण न फैल सके।

सवा सात सौ मेडिकल आफिसरों की भर्ती अटकी

इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। कोरोना काल में प्रदेश में चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों की कमी महसूस की जा रही है। सवा सात सौ से ज्यादा डाक्टरों की भर्ती सिर्फ इंटरव्यू की देरी के कारण अटकी हुई है। फरवरी में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए मप्र लोकसेवा आयोग (पीएससी) ने 727 मेडिकल आफिसरों की भर्ती की घोषणा की थी। इंटरव्यू के आधार पर सीधे चयन किया जाना था। इंटरव्यू प्रक्रिया अटकी हुई है। कोरोना के बढ़ते खतरे और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के बीच यदि इन डाक्टरों की भर्ती हो जाए तो प्रदेश को बड़ी राहत मिल सकती है।

मप्र लोकसेवा आयोग ने फरवरी में मेडिकल आफिसरों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। 14 मार्च तक आवेदन जमा भी हो गए। इसके बाद इंटरव्यू होना था और नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए जाते। इन पदों के लिए एमबीबीएस डिग्रीधारी चिकित्सकों से आवेदन मंगवाए गए थे। वर्षों बाद मेडिकल आफिसरों के इतने पदों पर एक साथ नियुक्ति की घोषणा हुई थी। पहले उम्मीद थी कि इंटरव्यू के बाद नियुक्तियां अप्रैल तक हो जातीं। हालांकि पीएससी ने अब तक चयन की प्रक्रिया और इंटरव्यू शुरू भी नहीं किए हैं। आवेदन दे चुके उम्मीदवारों के साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े जानकार भी मांग कर रहे हैं कि शासन को तुरंत प्रक्रिया शुरू कर इन डाक्टरों की भर्ती करनी चाहिए। इससे प्रदेश के सरकारी अस्पतालों को डाक्टरों का बड़ा अमला मिल सकेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। पीएससी तक भी यह बात पहुंचाई गई है कि कोरोना कर्फ्यू में यूं तो सभी प्रक्रिया बंद हैं लेकिन प्रदेश की स्थिति और स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरतों के मद्देनजर इस प्रक्रिया को तुरंत अंजाम पर पहुंचाया जाना चाहिए।

स्लाट में करें इंटरव्यू : पीएससी को सुझाव दिया गया है कि क्योंकि प्रदेश को अभी डाक्टरों की जरूरत है, ऐसे में इस भर्ती प्रक्रिया को तुरंत निपटा लिया जाना चाहिए। सिर्फ इंटरव्यू का एक दौर ही होना है। पीएससी चाहे तो कई इंटरव्यू बोर्ड बनाकर बहुत छोटे-छोटे हिस्सों में गिनती के उम्मीदवारों को बुलाकर इंटरव्यू लिए जा सकते हैं। इससे शारीरिक दूरी का पालन भी होगा और नियुक्तियां होने से प्रदेश को मदद भी मिल जाएगी।

आपात स्थिति का हवाला देकर जल्द इंटरव्यू करवाने की मांग

होटल-परिवहन बंद होने से परेशानी

पीएससी के अधिकारियों का कहना है कि आयोग अपनी ओर से प्रक्रिया को टालना या लंबित रखना नहीं चाहता था। लेकिन कोरोना के कारण बंद हुई गतिविधियां इसके आड़े आ रही हैं। दरअसल परिवहन से लेकर होटल व खाने-पीने की गतिविधियां भी पूरी तरह बंद हैं। ऐसे में पीएससी इंटरव्यू बोर्ड के सदस्यों को बुलाता है तो उन्हें ठहराने और खिलाने-पिलाने की व्यवस्थाएं मुश्किल हो जाएंगी। इंटरव्यू में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए परिवहन सुविधाएं बंद होने के कारण उनका आना भी मुश्किल होगा। ऐसे में तुरंत प्रक्रिया करवाना मुश्किल हो रहा है। इन इंटरव्यू को वर्चुअल माध्यम से करवाना भी संभव नहीं है। हालांकि पीएससी की सचिव वंदना वैद्य व अन्य अधिकारियों ने इस मामले पर आधिकारिक रूप से कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है।

एंकर स्टोरी

बिना अतिरिक्त फीस तीस मई तक छात्र भर सकेंगे परीक्षा फार्म

छात्रों से वसूली करोड़ों की लेट फीस अब वापस करेंगे विवि

कार्यालय प्रतिनिधि, भोपाल। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों की यूजी-पीजी की परीक्षाएं ओपन बुक सिस्टम से होंगी। ये परीक्षाएं जून और जुलाई में होंगी। इसके बाद भी विश्वविद्यालयों ने अप्रैल और मई में विद्यार्थियों से हजार-हजार रुपए विलंब और विशेष विलंब शुल्क लेकर परीक्षा फार्म जमा कराए हैं। इससे विश्वविद्यालयों के खातों में करोड़ों रुपए जमा हो गये हैं, जो अब उन्हें विद्यार्थियों को वापस करना होंगे। कोरोना संक्रमण में विद्यार्थी और उनके घर परिवार के सदस्य एक-एक रुपए के लिए परेशान हो रहे हैं। इसके बाद भी प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों ने परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों से सामान्य फीस के साथ 300 से एक हजार रुपए तक का विलंब और विशेष विलंब फीस लगाकर परीक्षा फार्म जमा करा लिये हैं। ये व्यवस्था अभी भी जारी है। प्रदेश के कालेजों और विवि में करीब बीस हजार विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किये हैं कि अब कोई भी विवि तीस मई तक बिना किसी विलंब शुल्क के परीक्षा फार्म जमा कराएगा। वर्तमान में जिन विवि ने विद्यार्थियों से अतिरिक्त फीस ली है, उन्हें 300 से एक हजार रुपए तक विलंब और विशेष विलंब शुल्क विद्यार्थियों को वापस करना होंगे। इस संबंध में सबसे ज्यादा शिकायतें जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर और अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा की दर्ज हुई हैं। जबकि बरकतउल्ला विश्वविद्यालय ने फीस जमा करने की अंतिम तिथि तीस मई कर रखा है। अब उच्च शिक्षा विभाग के आदेश के बाद बीयू को अंतिम तिथि में दस दिन की बढ़ोतरी करना होगी।

आर्थिक स्थिति हुई खराब: कोरोना संक्रमण में लगे कोरोना कर्फ्यू ने लोगों की आर्थिक कमर तोड़ दी है। ऐसे में छात्रों के माता-पिता फीस जमा करने की स्थिति में नहीं है। इसके बाद भी विवि छात्रों से परीक्षा के लिए 300 से 1000 रुपए का अतिरिक्त शुल्क जमा करा रहे हैं। इससे विवि के खजाने तो भर रहे हैं, लेकिन इसका असर मध्यम और कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के परिवार पर पड़ रहा है। फीस वापस होने से उन्हें कुछ समय की राहत जरूर मिल सकती है। वहीं हजारों विद्यार्थी जो विलंब शुल्क के अभाव में फीस जमा करने वंचित रह गये हैं, उन्हें भी तीस मई तक फार्म जमा करने का मौका मिल जाएगा।

भोज में 15 मई से आनलाइन जमा होंगे फार्म: सूबे के सभी विवि विद्यार्थियों की परीक्षाएं ओपन बुक सिस्टम से लेगी। इसके तहत भोज विवि ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। परीक्षाएं जून के दूसरे सप्ताह से शुरू हो सकती हैं। परीक्षाओं में शामिल होने विवि 15 मई से 15 जून तक आनलाइन आवेदन जमा कराएगा। इसके बाद यूजी-पीजी की परीक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी। परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की कापियां प्रदेश के सभी जिलों के 417 कालेजों में जमा हो सकेंगी। विद्यार्थी 11 रीजनल केंद्रों में भी कापियां जमा कर सकते हैं।

ओपन बुक पद्धति से हुई थी परीक्षा छात्रों का आरोप- कम दिए अंक

एलएलबी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को कम अंक मिलने पर उठाए सवाल

जागरण विदिशा

जैन कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लंबे समय से छात्रों के हितों को लेकर आंदोलन करती रही है। जिसके परिणाम स्वरूप कुछ समस्याओं का हल महाविद्यालय प्रशासन द्वारा किया गया।

किंतु छात्रों का कहना है कि एबीवीपी के छात्रों को एलएलबी की प्रथम वर्ष की परीक्षा में अन्य छात्रों की अपेक्षा कम अंक दिए गए हैं। इसमें एक छात्र को पूर्ण रूप से पास नहीं किया गया जिससे कि वह अगले वर्ष की परीक्षा से वंचित रह जाएगा। छात्रों का कहना है कि ओपन बुक पद्धति से परीक्षा होने के बाद भी आंदोलन कर रहे छात्रों को महाविद्यालय प्रशासन द्वारा पक्षपातपूर्ण रवैये से कम नंबर दिए गए हैं। विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री राहुल गुर्जर ने बताया कि महाविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्रों को जानबूझकर अन्य छात्रों की अपेक्षा परीक्षा में कम अंक दिए गए हैं, जिसकी विद्यार्थी परिषद निंदा करती है और इस संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन से बात करने के बाद राज्यपाल एवं उच्च शिक्षा मंत्री को महाविद्यालय प्रशासन की शिकायत की जाएगी।

ओपन बुक से होंगी स्नातक व स्नातकोत्तर की परीक्षाएं

विदिशा। कोविड.19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्नातक प्रथमए द्वितीय व तृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर की समस्त परीक्षाएं ओपन बुक पद्धति से आयोजित की जाएगी। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने नई गाईडलाईन जारी कर दी है। जारी गाईडलाईन के अनुसार स्नातक तृतीय वर्ष व स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा जून में आयोजित होगी और जुलाई में रिजल्ट घोषित किया जाएगा। वहीं स्नातक प्रथम व द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं जुलाई में आयोजित की जाएगी तथा परीक्षा परिणाम अगस्त में घोषित किया जाएगा। संबंधित विश्वविद्यालय वेबसाईट पर पेपर अपलोड करेगा। पेपर अपलोड होने के बाद विद्यार्थियों को कापियां घर पर लिखनी होगी और कलेक्शन सेंटर पर कापी जमा करनी होगी।

उच्च शिक्षा विभाग ने बढ़ा दी आवेदन की तिथि, इससे बीयू में बढ़ सकते हैं प्राइवेट परीक्षार्थी

प्रथम वर्ष में साढ़े 12 हजार, दूसरे और तीसरे में करीब 30 हजार विद्यार्थियों ने किए हैं आवेदन

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

ओपन बुक सिस्टम से आयोजित होने वाली बीयू की प्रथम वर्ष की प्राइवेट परीक्षा में शामिल होने के लिए अब तक करीब साढ़े 12 हजार विद्यार्थियों ने आवेदन किए हैं। वहीं दूसरे और तीसरे वर्ष में करीब 30 हजार प्राइवेट विद्यार्थियों द्वारा आवेदन किए गए हैं। हालांकि अब उच्च शिक्षा विभाग ने आवेदन की तारीख 31 मई कर दी है। इसके बाद प्राइवेट स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ने संभावना जताई जा रही है।

दरअसल, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय अपनी सभी परीक्षाएं इस बार ओपन बुक सिस्टम से लेगा। प्राइवेट परीक्षाएं नियमित विद्यार्थियों के साथ ओपन बुक सिस्टम से ही कराई जाएंगी। प्रथम से तीसरे वर्ष की प्राइवेट परीक्षा में करीब 42 हजार विद्यार्थी शामिल होंगे। बीयू 225 केंद्रों पर यूजी-पीजी की परीक्षाओं की कॉपियां जमा कराएगा। नोडल कॉलेज प्रोफेसरों की टीम बनाकर उक्त कॉलेजों से कॉपियां अपने पास बुलाएगा। इसके बाद बीयू अपने गोपनीय वाहन से मूल्यांकन कराने लेकर आएगा। बीयू की सीमाओं से बाहर रहने वाले विद्यार्थी उपकुलसचिव के नाम से डाक के माध्यम से कॉपियों को बीयू भेज सकते हैं।

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय अपनी सभी परीक्षाएं इस बार ओपन बुक सिस्टम से लेगा, प्राइवेट परीक्षाएं नियमित विद्यार्थियों के साथ ओपन बुक सिस्टम से ही कराई जाएंगी, प्रथम से तीसरे वर्ष की प्राइवेट परीक्षा में करीब 42 हजार विद्यार्थी शामिल होंगे

20 मई तक का दिया गया था समय

बीते दिनों ही बीयू द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की वार्षिक परीक्षा एवं पूरक परीक्षा के लिए आवेदन की समय-सीमा तारीख जारी की गई है। इसके अनुसार बीए, बीकॉम, बीएससी, होमसाइंस, बीए ऑनर्स, बीबीए, बीसीए, बीकॉम आनर्स के विद्यार्थियों के लिए बीस मई तक फार्म जमा करने का समय दिया गया था। वहीं एक हजार रुपये विशेष विलंब शुल्क के साथ 31 मई तक का समय दिया गया था। अब विभाग की ओर से इस संबंध में आवेदन की तारीख बढ़ाने का निर्णय होने के बाद तारीख बढ़ाई जाएगी।

जून-जुलाई में होंगी परीक्षाएं

प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना को देखते हुए यूजी-पीजी की परीक्षाएं जून और जुलाई में आयोजित की जाएंगी। यह परीक्षा ओपन बुक सिस्टम के तहत आयोजित होगी। यूजी फाइनल ईयर और पीजी फाइनल ईयर के चौथे सेमेस्टर के छात्रों की परीक्षा जून 2021 में आयोजित होगी। इसका परिणाम जुलाई में घोषित होगा। यूजी प्रथम और द्वितीय वर्ष और पीजी द्वितीय सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा जुलाई में आयोजित की जाएगी। इन परीक्षाओं के परिणाम अगस्त में घोषित किए जाएंगे। इन छात्रों के लिए प्रायोगिक परीक्षाएं लिखित परीक्षा के बाद आयोजित की जाएगी।

इधर, यूजीसी ने परीक्षाओं का फैसला कॉलेजों पर छोड़ा

कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे प्रकरणों के बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने फिलहाल परीक्षाओं से जुड़ा फैसला विश्वविद्यालयों पर छोड़ा है। ऐसे में अधिकतर विश्वविद्यालयों ने अंतिम वर्ष को छोड़कर बाकी सभी छात्रों को बगैर परीक्षा के ही अगली कक्षाओं में प्रमोट करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए विश्वविद्यालयों ने यूजीसी की ओर से पिछले साल परीक्षाओं को लेकर तय की गई गाइडलाइन को आधार बनाया है। लेकिन, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय (बीयू) को यूजीसी गाइडलाइन के साथ प्रदेश सरकार के आदेश का इंतजार है। प्रदेश सरकार के आदेश के बाद बीयू ने आगामी सभी परीक्षाएं जून-जुलाई में ओपन बुक पैटर्न पर कराने की आदेश जारी कर दिए हैं। बीयू के रजिस्ट्रार डॉ. आईके मंसूरी का कहना है कि यह स्टेट यूनिवर्सिटी है, यहां यूजीसी की गाइडलाइन के साथ राज्य सरकार के आदेश का पालन किया जाता है। हमने प्रदेश सरकार के आदेश के अनुसार सभी कक्षाओं के ओपन बुक एग्जाम कराने की तैयारी कर ली है। अब यूजीसी की नई गाइडलाइन के बाद प्रदेश सरकार के जो भी आदेश होंगे, उनका पालन किया जाएगा।

उच्च शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी

यूजी-पीजी स्टूडेंट 31 तक बिना लेट फीस कर सकेंगे आवेदन

पीपुल्स संवाददाता ● भोपाल

editor@peoplessamachar.co.in

प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों की यूजी और पीजी में परीक्षा फार्म नहीं भर पाने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। ऐसे सभी छात्र अब परीक्षा में बैठ पाएंगे। इसके लिए उन्हें लेट फीस भी नहीं देना होगा।

इस बारे में मध्यप्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को बाकायदा बयान जारी किया। उन्होंने वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि यूजी और पीजी के छात्र जो आगामी परीक्षा में बैठने वाले हैं। उनमें से कई छात्र परीक्षा फार्म नहीं भर पाए हैं। लेट फीस होने के बाद भी परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए हैं। उन्हें हम एक और मौका देने जा रहे हैं। वे सभी छात्र अब 31 मई तक बिना कोई लेट फीस दिए परीक्षा फार्म भर सकेंगे। इससे सभी परीक्षा में बैठ सकेंगे। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को निर्देश दिए हैं कि वे समय सीमा में परीक्षा कार्यक्रम को लागू करें। उल्लेखनीय है कि यूजी अंतिम वर्ष पीजी चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं जून 2021 में आयोजित की जाएंगी।

ओपन बुक परीक्षाओं के फार्म 30 तक भरे जा सकेंगे

- जेयू ने यूजी थर्ड ईयर व पीजी फोर्थ सेम के फार्म भरने की तारीख 20 मई तय की है

पीपुल्स संवाददाता • ग्वालियर
editor@peoplessamachar.co.in

उच्च शिक्षा विभाग ने जीवाजी विवि सहित प्रदेश भर के पारंपरिक विश्वविद्यालयों को स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षाएं ओपन बुक पद्धति से जून माह में कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। जेयू ने दोनों परीक्षाओं में शामिल होने वाले ऐसे छात्र-छात्राएं, जिन्होंने परीक्षा फार्म नहीं भरे हैं, उनके लिए फार्म भरने की अंतिम तारीख 20 मई

तय कर दी है, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग ने फार्म भरने की तारीख बढ़ाकर 30 मई कर दी है। विभाग ने इसे लेकर विश्वविद्यालयों को बुधवार को निर्देश जारी कर दिए हैं। स्नातक थर्ड ईयर व स्नातकोत्तर फोर्थ सेम की परीक्षा की परीक्षा जून में होगी और इसका रिजल्ट जुलाई में आएगा, जबकि स्नातक फर्स्ट-सेकंड ईयर व स्नातकोत्तर सेकंड सेम की परीक्षा जुलाई में होगी और रिजल्ट अगस्त में आएगा। परीक्षाएं लेट होने के कारण सत्र 21-22 लेट हो जाएगा। ऑनलाइन एडमिशन स्नातक थर्ड ईयर के रिजल्ट निकलने के बाद ही शुरू हो पाएंगे, क्योंकि पास होने वाले छात्र स्नातकोत्तर में प्रवेश लेंगे।

फोन नहीं उठाने वाले कर्मचारी अनुपस्थित समझे जाएंगे

जिला प्रशासन के निर्देशानुसार जीवाजी विवि में 10 फीसदी स्टाफ ही रहा है। जो अधिकारी-कर्मचारी विवि नहीं आ रहे हैं, उन्हें फोन पर उपलब्ध रहने के निर्देश जारी किए हैं ताकि विवि का काम प्रभावित नहीं हो। कर्मचारियों के फोन नहीं उठाने पर परीक्षा नियंत्रक प्रो. उमेश होलानी ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा है कि स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षाएं होने वाली हैं साथ ही सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें काफी बढ़ गई हैं मगर कर्मचारी इन्हें गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। कर्मचारियों को जरूत पड़ने पर फोन लगाए जा रहे हैं मगर वह फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। ऐसा करना अनुशासनहीनता की श्रेणी में है, इसलिए फोन नहीं उठाने वाले कर्मचारियों को अनुपस्थित माना जाएगा और उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

इनका कहना है

उच्च शिक्षा विभाग के आदेश पर स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाओं के फार्म भरने की तारीख 20 से बढ़ाकर 30 मई कर दी है।

प्रो. उमेश होलानी
रेक्टर, जेयू

यूजी-पीजी स्टूडेंट 31 तक बिना लेट फीस कर सकेंगे आवेदन

उच्चशिक्षा मंत्री ने कुलपतियों को दिए निर्देश

पीपुल्स संवाददाता ● भोपाल

editor@peoplessamachar.co.in

प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों की यूजी और पीजी में परीक्षा फार्म नहीं भर पाने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। ऐसे सभी छात्र अब परीक्षा में बैठ पाएंगे। इसके लिए उन्हें लेट फीस भी नहीं देना होगा।

इस बारे में मध्यप्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को बाकायदा बयान जारी किया। उन्होंने वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि यूजी और पीजी के छात्र जो आगामी परीक्षा में बैठने वाले हैं। उनमें से कई छात्र परीक्षा फार्म नहीं भर पाए हैं। लेट फीस होने के बाद भी परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए हैं। उन्हें हम एक और मौका देने जा रहे हैं। वे सभी छात्र अब 31 मई तक बिना कोई लेट फीस दिए परीक्षा फार्म भर सकेंगे। इससे सभी परीक्षा में बैठ सकेंगे। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को निर्देश दिए हैं कि वे समय सीमा में परीक्षा कार्यक्रम को लागू करें। उल्लेखनीय है कि यूजी अंतिम वर्ष पीजी चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं जून 2021 में आयोजित की जाएंगी। परीक्षा परिणाम जुलाई 2021 में घोषित किया जाएगा। पीजी प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और पीजी द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं जुलाई 2021 आयोजित की जाएंगी।

अधिकांश विवि द्वारा अंतिम वर्ष को छोड़कर सभी कक्षाओं में प्रमोट करने की तैयारी

यूजीसी ने विवि पर छोड़ा एग्जाम का फैसला

पीपुल्स संवाददाता ● भोपाल
मो.नं. 9893231237

कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे प्रकरणों के बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने फिलहाल परीक्षाओं से जुड़ा फैसला विश्वविद्यालयों पर छोड़ दिया है। विवि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार परीक्षाएं कराने या फिर छात्रों को सीधे प्रमोट करने का फैसला ले सकेंगे। देश भर के ज्यादातर विश्वविद्यालयों ने अंतिम वर्ष को छोड़कर बाकी सभी छात्रों को बगैर परीक्षा के ही अगली कक्षाओं में प्रमोट करने की तैयारी कर ली है। लेकिन, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय (बीयू) को यूजीसी गाइडलाइन के साथ प्रदेश सरकार के आदेश का इंतजार है। इसके

लिए विश्वविद्यालयों ने यूजीसी की ओर से पिछले साल परीक्षा गाइडलाइन को आधार बनाया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार के आदेश के बाद बीयू ने सभी परीक्षाएं जून-जुलाई में ओपन बुक पैटर्न से कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकिक यूजीसी गाइडलाइन नहीं आने से असमंजस बना हुआ थी। अब यदि प्रदेश सरकार यूजीसी की गाइड लाइन के अनुसार आदेश जारी करती है तो फिर बीयू की भी केवल अंतिम वर्ष और ईयर की परीक्षाएं होंगी। वहीं दूसरी ओर देश के जिन विवि ने अंतिम वर्ष के अलावा अन्य कक्षाओं में प्रमोशन देने की तैयारी की थी, उनके निर्णय पर अब यूजीसी की मुहर लग गई है। यूजीसी के सचिव डॉ. रजनीश जैन के मुताबिक विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्थान होते हैं। ऐसे में उन्हें परीक्षाओं और शैक्षणिक सत्र आदि को लेकर अपने स्तर पर कोई भी फैसला लेने का पूरा अधिकार है। यूजीसी का कहना है कि संक्रमण का प्रभाव देश में कम और ज्यादा है। ऐसे में परीक्षा की स्टैंडर्ड गाइडलाइन नहीं बनाई गई है। इस बीच, विश्वविद्यालयों ने स्नातक के पहले और दूसरे वर्ष के आंतरिक आंकलन या फिर पिछले साल के प्रदर्शन के आधार पर प्रमोट करने की तैयारी शुरू कर दी है।

सीबीएसई दोस्त फार लाइफ

सीबीएसई ने विद्यार्थियों के मानसिक तनाव को देखते हुए ""सीबीएसई दोस्त फार लाइफ"" एप लांच किया है। इस एप के माध्यम से छात्रों और अभिभावकों को मनोवैज्ञानिक परामर्श दिए जाएंगे। यह एप विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा और उन्हें 12वीं के बाद करियर विकल्प से संबंधित सलाह भी देगा।

स्टेट यूनिवर्सिटी होने से यूजीसी के साथ राज्य शासन के आदेश का पालन होता है। हमने प्रदेश सरकार के आदेश के अनुसार सभी कक्षाओं के ओपन बुक एग्जाम कराने की तैयारी कर ली है। अब यूजीसी की नई गाइडलाइन के बाद प्रदेश सरकार के जो भी आदेश होंगे, उनका पालन किया जाएगा।
डॉ. एचएस त्रिपाठी, रजिस्ट्रार, बीयू, भोपाल

जहां पॉजिविटी रेट 5% से कम वहां हटा सकेंगे कोरोना कर्फ्यू : शिवराज

कहा- मई में शादी ब्याह जैसे आयोजन छोटे स्तर पर किए जाएं

पीपुल्स ब्यूरो ● भोपाल
मो.नं. 9425078939

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कहा कि जहां कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी दर 5 प्रतिशत से नीचे आ गई है वहां 17 मई के बाद धीरे-धीरे वैज्ञानिक ढंग से कोरोना कर्फ्यू हटाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि यह वायरस हमारे व्यवहार से ज्यादा फैलता है। यदि हम शादी ब्याह, भीड़ और बड़े समारोह भीड़ में गए तो कोरोना संक्रमण तेज गति से फैलता है। जन-सहयोग से

लागू कोरोना कर्फ्यू जब तक है तब तक कोई भी घरों से बाहर नहीं निकले। मई माह में शादी-ब्याह नहीं करें। जून माह में कोरोना संक्रमण नियंत्रित होने पर शादी-ब्याह आदि आयोजन छोटे स्तर पर किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण कुछ गांवों में भी फैला है। इसे नियंत्रित करने के लिए किल कोरोना अभियान चल रहा है। अमला मेहनत के साथ घर-घर दस्तक दे रहा है।

मप्र में ब्लैक फंगस के 50 मरीज, इलाज में मदद करेगी सरकार

प्रदेश में ब्लैक फंगस के संक्रमण की घटनाएं सामने आ रही हैं, जो बहुत भयानक है। प्रदेश में 50 रोगियों की पुष्टि हुई है। यह चिंता का विषय है। इसमें नाक, मुंह, दांत, आंख मस्तिष्क और बाकी अंग भी संक्रमित हो जाते हैं। इलाज प्रोटोकॉल के अनुसार उपचार सुनिश्चित किया जाए। जो लोग आर्थिक कमजोर हैं, उनके निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की जाएगी और सरकार ऐसे पेशेंट को भरपूर सहयोग करेगी।

दैनिक भास्कर भोपाल 13-05-2021

गुना, छिंदवाड़ा, भिंड, बुरहानपुर और खंडवा में 17 मई के बाद कर्फ्यू से ढील देने की तैयारी

यहां संक्रमण दर 5% या इससे कम, जून में सीमित शादी-ब्याह की छूट

पॉलिटिकल रिपोर्टर . भोपाल | मप्र के पांच जिलों में पॉजिटिविटी रेट पांच प्रतिशत या इससे कम हो गया है। यह स्थिति लगातार एक सप्ताह से बनी हुई है। राज्य सरकार ने इसे देखते हुए 17 मई के बाद इन जिलों में कोरोना कर्फ्यू से राहत देने की तैयारी की है। यहां के जिला क्राइसिस मैनेजमेंट समूहों ने अपने प्रस्ताव भेजे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनसे चर्चा करके मंजूरी देंगे। हालांकि उन्होंने बुधवार को कोरोना समीक्षा बैठक में इसके संकेत भी दिए कि इन जिलों में वैज्ञानिक तरीके से छूट दी जाएगी।

5% से कम संक्रमण तो नियंत्रण के संकेत

अंतरराष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार यदि पॉजिटिविटी रेट 5% से नीचे आती है तो यह संक्रमण के नियंत्रित होने का संकेत है। ऐसे जिले जहां यह रेट 5 प्रतिशत से नीचे हैं, उनमें गुना, छिंदवाड़ा, भिंड, बुरहानपुर और खंडवा जिले हैं। यहां धीरे-धीरे कर्फ्यू हटाया जाएगा। जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट बढ़ा रहेगा, वहां कोरोना कर्फ्यू नहीं खुलेगा। जिला, ब्लॉक, ग्राम और शहर के वार्ड स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों का गठन किया गया है।

एनटीए ने बढ़ाई होटल मैनेजमेंट प्रवेश परीक्षा की तारीख

भोपाल। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने होटल मैनेजमेंट में प्रवेश के लिए आयोजित एंट्रेंस एग्जाम में आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 12 जून कर दी गई है। कोविड के चलते स्टूडेंट्स के लिए यह सुविधा दी गई है क्योंकि कई कारणों से स्टूडेंट्स इस समय आवेदन नहीं कर पा रहे। इसके अलावा स्टूडेंट्स को बताया गया है कि वे अपने फॉर्म में 2 से 8 जून तक करेक्शन कर सकेंगे। इस प्रवेश परीक्षा का सिलेबस एनटीए की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड एनालिटिकल एप्टीट्यूड से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। इसमें कुल 200 सवाल होते हैं।

अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस पर विधायक पीसी शर्मा ने नर्सों को किया सम्मानित

नर्सिंग शब्द को सुनकर मन में सेवा और समर्पण का भाव आता है: पीसी शर्मा

भोपाल(आरएनएन)। पूर्व मंत्री एवं विधायक पीसी शर्मा ने दक्षिण पश्चिम विधानसभा अंतर्गत आने वाले कुटकुट भवन, शासकीय सरदार पटेल नवीन हाई स्कूल पंचशील नगर, नवीन कन्या हाईस्कूल नेहरु नगर, सरस्वती शिशु मंदिर तुलसी नगर में कोविड टीकाकरण कार्य निरीक्षण किया। कुटकुट भवन में टीकाकरण कार्य का निरीक्षण करने के दौरान विधायक पीसी शर्मा ने अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के मौके पर दुनिया भर में कोरोना वैश्विक महामारी के समय अस्पतालों में और टीकाकरण अभियान में दिन रात सेवाएं देने पर उनको शुभकामनाएं देते हुए फूल की मालाओं से नर्सों को सम्मानित कर उन्हें प्रणाम किया। इस मौके पर शर्मा ने कहा कि नर्सिंग शब्द का अर्थ चाहे जो हो लेकिन इस शब्द को सुनकर मन में भाव सेवा और समर्पण का आता है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में डॉक्टर स्वास्थ्य प्रणाली में केन्द्र की भूमिका में रहे वही नर्सों ने इस महामारी में कंधे से कंधा मिलाकर स्वास्थ्य सेवाओं में अतुलनीय योगदान दिया है। इसलिए आज अंतरराष्ट्रीय दिवस पर मैं सभी नर्स बहनों को श्रद्धाभाव से प्रणाम करता हूं। इस मौके पर उनके साथ पूर्व पार्षद गुड्डू चौहान, पूर्व पार्षद मोनू सक्सेना, नमिता गौर जिला अध्यक्ष कांग्रेस सेवादल, राकेश यादव, अमित समैया, रमेश साहबानी मौजूद रहे।

डीआरएम नें मंडल की सभी नर्सों के योगदान की सराहना की

भोपाल। मंडल रेल प्रबंधक उदय बोरवणकर नें बुधवार को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस पर मंडल की सभी नर्सिंग कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर डीआरएम नें मंडल की सभी नर्सिंग कर्मचारियों द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं में दिए जा रहे योगदान, उनके द्वारा किये जा रहे जोखिम भरे काम की सराहना की और इसके लिए उनको हृदय से धन्यवाद भी दिया। ज्ञात हो कि कोरोना की कठिन परिस्थिति में गत एक वर्ष से ज्यादा से नर्सिंग कर्मचारियों ने निरंतर काम करके रेलवे कर्मचारियों की सेहत का ध्यान रखा है। कई कर्मचारियों नें उपचार होने के बाद उनके इस निःस्वार्थ सेवा की प्रशंसा की है।

वर्चुअल माध्यम से अधिकारियों को कराया ध्यान, योग का अभ्यास

भोपाल। मंडल रेल प्रबंधक उदय बोरवणकर के निर्देशन व मार्गदर्शन में भोपाल रेल मंडल द्वारा कोविड-19 के संक्रमण से निपटने और अपने अधिकारियों व कर्मचारियों को संक्रमण के प्रभाव से बचाने के लिए विभिन्न गतिविधियों द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को मंडल के समस्त रेल अधिकारियों के लिए वर्चुअल रिलेक्सेशन और मेडिटेशन के प्रयोगिक सत्र का आयोजन किया गया। जिसमें अंतरराष्ट्रीय हार्ट फुलनेस संस्थान, हैदराबाद के प्रेस्पेक्टर डॉक्टर कमल वाधवा के द्वारा कोरोना महामारी से उत्पन्न तनाव, भय को दूर करने के लिए रिलैक्सेशन तकनीक के द्वारा ध्यान विधि का वर्चुअल अभ्यास कराया गया। जिसमें कोरोना से भय के माहौल में मानसिक रूप से किस तरह सशक्त रहें और अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति और मानसिक स्तर को किस तरह ऊंचा बनाए रखें, इस बारे में टिप्स दिए गए तथा प्रायोगिक ध्यान का अभ्यास भी कराया गया। इस कार्यक्रम में मंडल के 50 से ज्यादा अधिकारी एवं उनके परिवार के सदस्य वर्चुअल रूप से उपस्थित होकर ध्यान एवं योग अभ्यास का भरपूर लाभ उठाया। इससे पूर्व यह प्रायोगिक सत्र इटारसी, बीना और गुना में कर्मचारियों के लिए आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों द्वारा वर्चुअल रूप उपस्थित होकर ध्यान, योग अभ्यास का भरपूर लाभ उठाया गया था।

सीबीएसई स्कूलों में इस सत्र में सिर्फ 20 फीसद एडमिशन

भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। कोरोना संक्रमण के कारण स्कूल बंद हैं। ऐसे में पिछले सत्र में अधिकांश स्कूलों में एडमिशन कम हुए थे। इस बार भी स्कूलों में वही स्थिति है। राजधानी के सीबीएसई स्कूलों में जनवरी से एडमिशन प्रक्रिया शुरू करने के कारण 15 से 20 फीसद एडमिशन ही हुए हैं, लेकिन एमपी बोर्ड के निजी व सरकारी स्कूलों में तो एडमिशन प्रक्रिया शुरू भी नहीं हो सकी है।

सीबीएसई स्कूलों में जनवरी से नए सत्र के एडमिशन शुरू हो जाते हैं। इसके चलते राजधानी के सहोदय ग्रुप के सभी स्कूलों में जनवरी और फरवरी में 15 से 20 फीसद बच्चों ने एडमिशन ले लिया है। इसके बाद कोरोना संक्रमण बढ़ा और स्कूल बंद होने के साथ ही एडमिशन प्रक्रिया रोक दी गई है। इन स्कूलों ने पिछले वर्ष मार्च तक अपने एडमिशन पूरे

कर लिए थे। दूसरी ओर कोरोना के कारण सालभर स्कूल व अभिभावकों के बीच फीस की लड़ाई चलती रही और कोर्ट व सरकार ने केवल शिक्षण शुल्क लेने के आदेश दिए थे। इस कारण भी एडमिशन नहीं हुए। कम एडमिशन होने पर अन एडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने जताई चिंता है।

स्कूलों में जनवरी से एडमिशन प्रक्रिया शुरू की गई थी। कोरोना संक्रमण बढ़ने पर प्रक्रिया धीमी चली और 20 फीसद ही एडमिशन हो पाए।

-**विनीराज मोदी**, अन एडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन

पेंशन कार्यालय में अफसरों ने रोका 15 कर्मियों का भुगतान, एक की मौत

पैसे के अभाव में उपचार न कराने पर दो की हालत बनी हुई है गंभीर

भोपाल ■ राज न्यूज नेटवर्क

कोषालय से लेकर पेंशन कार्यालय तक भ्रष्टाचार दीमक की तरह सिस्टम को निगल रहा है। ताजा मामला लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का है। जहां पर अनुरक्षण खंड एवं परियोजना क्रमांक 1 के दिसंबर में 15 कर्मचारी रिटायर हुए थे लेकिन आज तक इनका पेंशन भुगतान नहीं किया गया है।

जबकि इन कर्मचारियों ने रिटायरमेंट के 1 महीने पहले नवंबर 2020 में पेंशन और ग्रेच्युटी का भुगतान कराने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से कंप्लीट प्रकरण कोषालय को भिजवाया था। यहां का अनुमोदन होने के उपरांत पेंशन कार्यालय को यह भुगतान करना था। दुर्भाग्य देखें कि पूरे 5 महीने निकल चुके हैं। रिटायरमेंट होने के बाद इन गरीब कर्मचारियों का भुगतान नहीं किया गया है। कुछ दिन पहले एक कर्मचारी बीमार हुआ। पैसे के अभाव में वह समय से उपचार नहीं करवा पाया और उसकी मौत हो गई। इस कर्मचारी का नाम भगवानदास मालवीय बताया जा रहा है। जबकि पेंशन एवं ग्रेच्युटी भुगतान की प्रतीक्षा कर रहे राजेंद्र कुमार तिवारी एवं देवीदास की हालत गंभीर बनी हुई है। यह दोनों कर्मचारी घातक बीमारी से जूझ रहे हैं लेकिन इनके पास पैसा नहीं है। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के संभागीय अध्यक्ष डीके गौर का कहना है कि इस संबंध में पूरी समस्या से कलेक्टर को भी अवगत करा दिया गया है लेकिन आज तक भुगतान नहीं हो पाया है। उन्होंने बताया है कि पैसे के अभाव में ही एक कर्मचारी की मौत हुई है। इस मामले में पेंशन कार्यालय की संभागीय अधिकारी यशोदा चौहान एवं कोषालय अधिकारी केके शर्मा से दो बार दूरभाष पर संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन इन दोनों ही अधिकारियों ने मोबाइल पर बात करना उचित नहीं समझा।

कार्यालयों में अधिकारियों की बिगड़ी आदतें

वरिष्ठ कर्मचारी नेता प्रमोद कुमार तिवारी ने आरोप लगाया है कि कोषालय और पेंशन कार्यालयों में अधिकारियों की आदतें शासकीय सेवकों द्वारा ही बिगाड़ दी गई है। उन्होंने कहा है कि यहां पर जल्दी काम कराने के चक्कर में कुछ कर्मचारी स्वयं रिश्वत का ऑफर देते हैं। जिसका खामियाजा पूरे कर्मचारी जगत को उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि भुगतान क्यों रोका गया है। सरकार को इस मामले की तत्काल जांच करवाकर दोषी अधिकारियों को कठोर दंड देना चाहिए। उनका का यह भी आरोप है कि कोषालय और पेंशन कार्यालयों में सालों से भ्रष्ट अधिकारी जमे हुए हैं। जिसके कारण निर्दोष कर्मचारियों को अपना ही भुगतान लेने के लिए चप्पल रगडनी पड़ रही है।

कोविड-19 नियमों का पालन न करने के कारण सिंधु मेडिकल स्टोर बैरागढ़ को किया सील

भोपाल। कोविड-19 गाइड लाइन एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने एवं अन्य शिकायतें मिलने पर अनुविभागीय अधिकारी के निर्देशन में ड्रग इंस्पेक्टर कैएल अग्रवाल, बैरागढ़ तहसीलदार गुलाब सिंह, इंस्पेक्टर रवीन्द्र, विभूति नारायण और पुलिस बल की उपस्थिति में भोपाल बैरागढ़ स्थित सिंधु मेडिकल स्टोर पर छापा मार कार्यवाही करते हुए संबंधित दुकान संचालक को नोटिस जारी कर दुकान को सील कर दिया गया है। दुकान को तुरंत प्रभाव से आगामी आदेश तक बंद किया गया है। दुकान संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, इसके बाद नियमानुसार लाइसेंस निलंबन, निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।

एंकर स्टोरी

बिना अतिरिक्त फीस तीस मई तक छात्र भर सकेंगे परीक्षा फार्म

छात्रों से वसूली करोड़ों की लेट फीस अब वापस करेंगे विवि

कार्यालय प्रतिनिधि, भोपाल। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों की यूजी-पीजी की परीक्षाएं ओपन बुक सिस्टम से होंगी। ये परीक्षाएं जून और जुलाई में होंगी। इसके बाद भी विश्वविद्यालयों ने अप्रैल और मई में विद्यार्थियों से हजार-हजार रुपए विलंब और विशेष विलंब शुल्क लेकर परीक्षा फार्म जमा कराए हैं। इससे विश्वविद्यालयों के खातों में करोड़ों रुपए जमा हो गये हैं, जो अब उन्हीं विद्यार्थियों को वापस करना होंगे। कोरोना संक्रमण में विद्यार्थी और उनके घर परिवार के सदस्य एक-एक रुपए के लिए परेशान हो रहे हैं। इसके बाद भी प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों ने परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों से सामान्य फीस के साथ 300 से एक हजार रुपए तक का विलंब और विशेष विलंब फीस लगाकर परीक्षा फार्म जमा करा लिये हैं। ये व्यवस्था अभी भी जारी है। प्रदेश के कालेजों और विवि में करीब बीस लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किये हैं कि अब कोई भी विवि तीस मई तक बिना किसी विलंब शुल्क के परीक्षा फार्म जमा कराएगा। वर्तमान में जिन विवि ने विद्यार्थियों से अतिरिक्त फीस ली है, उन्हें 300 से एक हजार रुपए तक विलंब और विशेष विलंब शुल्क विद्यार्थियों को वापस करना होगी। इस संबंध में सबसे ज्यादा शिकायतें जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर और अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा की दर्ज हुई हैं। जबकि बरकतउल्ला विश्वविद्यालय ने फीस जमा करने की अंतिम तिथि बीस मई कर रखा है। अब उच्च शिक्षा विभाग के आदेश के बाद बीयू को अंतिम तिथि में दस दिन की बढ़ोत्तरी करना होगी।

आर्थिक स्थिति हुई खराब: कोरोना संक्रमण में लगे कोरोना कर्फ्यू ने लोगों की आर्थिक कमर तोड़ दी है। ऐसे में छात्रों के माता-पिता फीस जमा करने की स्थिति में नहीं है। इसके बाद भी विवि छात्रों से परीक्षा के लिए 300 से 1000 रुपए का अतिरिक्त शुल्क जमा करा रहे हैं। इससे विवि के खजाने तो भर रहे हैं, लेकिन इसका असर मध्यम और कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के परिवार पर पड़ रहा है। फीस वापस होने से उन्हें कुछ समय को राहत जरूर मिल सकती है। वहीं हजारों विद्यार्थी जो विलंब शुल्क के अभाव में फीस जमा करने वंचित रह गये हैं, उन्हें भी तीस मई तक फार्म जमा करने का मौका मिल जाएगा।

कॉलेज में 15 मई से आनलाइन जमा होंगे फार्म: सूबे के सभी विवि विद्यार्थियों की परीक्षाएं ओपन बुक सिस्टम से लेंगे। इसके तहत बीयू विवि ने तैयारियां शुरू कर दी है। परीक्षाएं जून के दूसरे सप्ताह से शुरू हो सकती हैं। परीक्षाओं में शामिल होने विवि 15 मई से 15 जून तक आनलाइन आवेदन जमा कराएगा। इसके बाद यूजी-पीजी की परीक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी। परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की कापियां प्रदेश के सभी जिलों के 417 कालेजों में जमा हो सकेंगी। विद्यार्थी 11 रीजनल सेंटरों में भी कापियां जमा कर सकते हैं।

कॉलेज छात्र 31 मई तक भर सकते हैं परीक्षा फॉर्म

बिना लेट फीस दिए परीक्षा में शामिल हो सकेंगे छात्र

भोपाल।मध्यपेदश के सभी यूजी और पीजी में परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। ऐसे सभी छात्र अब परीक्षा में बैठ पाएंगे। इसके लिए उन्हें लेट फीस भी नहीं देना होगा। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने इस संबंध में बुधवार को बयान जारी किया। उन्होंने वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि यूजी और पीजी के छात्र जो आगामी परीक्षा में बैठने वाले हैं। उनमें से कई छात्र परीक्षा फार्म नहीं भर पाए हैं। लेट फीस होने के बाद भी परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए हैं। उन्हें हम एक और मौका देने जा रहे हैं। वे सभी छात्र अब 31 मई तक बिना कोई लेट फीस दिए परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे। इससे सभी परीक्षा में बैठ सकेंगे।

इसके साथ ही प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय के सभी कुलपति भी समय सीमा में परीक्षा कार्यक्रम को लागू करें। स्नातक अंतिम वर्ष/स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं जून 2021 में आयोजित की जाएंगी। परीक्षा परिणाम जुलाई 2021 में घोषित किया जाएगा।

एनआईओएस बोर्ड परीक्षा के लिए अब 15 तक जमा होगी फीस

भोपाल। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ने एनआईओएस बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए फीस जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ा कर 15 मई की रात तक कर दी है। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक फीस जमा नहीं की है, उनके लिए यह अंतिम मौका है। जिन अभ्यर्थियों ने 10वीं और 12वीं कक्षा की जून 21 परीक्षा के लिए आवेदन नहीं किया है, वे भी admis.nios.ac.in के जरिए 10वीं और 12वीं कोर्स की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं।

सुविधा

लोकसभा-राज्यसभा टीवी मिलाकर बनाया जाएगा 'संसद टीवी'

अनुपम खेर, आशुतोष राणा जैसे दिग्गज करेंगे एंकरिंग

नई दिल्ली, ब्यूरो। लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मिलाकर एक नया चैनल बनाने की कवायद शुरू हुई है। दावा किया जा रहा है कि इस चैनल की गुणवत्ता बीबीसी और नेशनल जियोग्राफिक जैसी होगी। इतना ही नहीं चैनल पर अनुपम खेर, शेखर कपूर, आशुतोष राणा, मनोज बाजपेई और रेणुका शहाणे जैसे जाने-माने फिल्म अभिनेता कार्यक्रम प्रस्तुत करते नजर आ सकते हैं।

संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रवि कपूर द्वारा भावी कार्यक्रमों की बनाई गई रूपरेखा के मुताबिक नए चैनल का प्रस्तुतीकरण और कार्यक्रमों की गुणवत्ता बीबीसी या नेशनल जियोग्राफिक जैसे विश्व स्तरीय चैनलों जैसी होगी। भावी एंकरों की सूची में इन अभिनेताओं के अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर, पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत, वित्त मंत्रालय में प्रमुख आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल, आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ विवेक देबराय, सामरिक मामलों के विशेषज्ञ मारूफ रजा, तीनों सेनाओं के मुख्य कमांडर जनरल बिपिन रावत, भाजपा सांसद वरुण गांधी, तेजस्वी सूर्या, राजीव चंद्रशेखर, जम्मू कश्मीर के पूर्व महाराजा कर्ण सिंह के अलावा टैक्सी सर्विस ओला के संस्थापक भाविश अग्रवाल और फ्रीचार्ज जैसी फिनटेक कंपनियों के संस्थापक कुणाल शाह को भी शामिल किया गया है।

दूसरे राज्यों से जुड़ गए तार, अलग-अलग थानों में विवेचना से आरोपियों को मिल सकता है लाभ

नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन इंटर स्टेट अपराध की जांच CBI से हो!

नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने वाले गिरोह की जड़ तक पहुंचने के लिए पुलिस मुख्यालय को अब सक्रिय होना होगा। बताया जाता है कि अलग-अलग राज्यों के अलग-अलग थानों में जांच होगी तो कई बार आरोपियों को दूसरी जगह की विवेचना का लाभ मिल जाता है। जबकि एक साथ एक ही एजेंसी इस पूरे मामले की जांच करेगी तो विवेचना भी मजबूत होगी और आरोपियों को सजा भी मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी।

पवन वर्मा, भोपाल

जबलपुर और इंदौर पुलिस ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। दोनों ही जिलों की पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को यह पता चला कि नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने और बेचने का खेल गुजरात से चल रहा है। इंदौर, जबलपुर के अलावा भी मध्य प्रदेश के कई जिलों में इस गिरोह ने घुसपैठ कर ली है। ऐसे में इस गिरोह को जड़ से पकड़ना अब जरूरी हो गया है।

नहीं है कानून में प्रावधान

नकली इंजेक्शन बेचने पर कानून में बहुत स्पष्ट प्रावधान नहीं है। जबलपुर पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 274 और 275 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। जिसमें सजा ही महज 6 महीने की है। हालांकि इसके साथ पुलिस ने आईपीसी की धारा 308 भी लगाई है। इसमें सात साल की सजा का प्रावधान है। पुलिस को अदालत में आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला साबित करना होगा।

आजीवन कारावास का प्रावधान की तैयारी

प्रदेश सरकार अब खाद्य अपमिश्रण अधिनियम में संशोधन करने की तैयारी में है। नकली इंजेक्शन और दवा बेचने के दोषियों को आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान इसमें किया जा सकता है। इसके लिए विधि विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसके बाद इस अधिनियम को संशोधित करने अंतिम रूप दिया जाएगा।

गहन जांच की मांग

नकली इंजेक्शन की बिक्री को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने भी जांच की मांग की है। हालांकि उन्होंने किसी विशेष एजेंसी से जांच की मांग न करते हुए गहन जांच की मांग प्रदेश सरकार से की है।

नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन का मामला अब इंटर स्टेट हो चुका है। प्रदेश में भी कुछ शहरों में इसके मामले सामने आए हैं। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लोगों के लिए जानलेवा हो रहा है, इसलिए इस मामले को सीबीआई से ही जांच करवाई जानी चाहिए।

एससी त्रिपाठी,
रिटायर्ड डीजीपी
मध्यप्रदेश

थाने में जांच हो रही है जांच के हर बिंदु पर फोकस होना चाहिए। इस मामले में किसी भी सूरत में आरोपी बचना नहीं चाहिए। जांच का सुपरविजन उच्च स्तर पर लगातार होते रहना चाहिए।

विजय वाते,
रिटायर्ड एडीजी

पंचायतों में जनता कर्फ्यू भी नहीं रोक पा रहा कोरोना स

बृजेन्द्र मिश्रा, भोपाल

प्रदेश में पंचायतों में जनता कर्फ्यू के लिए संकल्प पत्र भरने के बाद भी कोरोना की एंट्री ग्रामीण इलाकों में रुक नहीं रही है। कई जिले ऐसे हैं जहां सौ फीसदी जनता कर्फ्यू ग्राम पंचायतों में लगाए जाने के बाद भी कोरोना संक्रमितों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इससे संक्रमण की चेन गांवों में टूटने के बजाय लम्बी होती जा रही है। किल कोरोना अभियान के अंतर्गत कराया जा रहा सर्वे भी इन ग्रामीणों के लिए राहतकारी साबित नहीं हो रहा है। ऐसे में बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए जनता कर्फ्यू का संकल्प पत्र भरने की पंचायतों की कार्यवाही औपचारिकता बनती दिख रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने गांवों में जनता कर्फ्यू लगाने की अपील सरपंचों और ग्रामीणजन से की थी। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने इसके लिए सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि संकल्प पत्र भरकर जनता कर्फ्यू लागू करने की जानकारी दें और उस पर सख्ती से अमल कराएं। इसके बाद प्रदेश की 22814 ग्राम पंचायतों में से 22378 पंचायतों ने संकल्प पत्र भरकर शासन को दे दिया कि उनके यहां जनता कर्फ्यू लागू है पर हकीकत इसमें अलग है।

सर्वाधिक जनता क
जिलों में कोरोना

कोरोना के सर्वाधिक प्रकरण
ग्रामीण क्षेत्रों में है जो 10 हज
पार कर गए हैं। इसके अल
पंचायतों वाले रीवा में 5315
पन्ना में 5331, देवास में
6861, छतरपुर में 4719,
बालाघाट में 4453, हो
विदिशा में 4084 कोरोना संक्र
इन जिलों में संकल्प पत्र भरक
लगाने की बात औपचारिकता

सरकार ने स्कूल छोड़ने संबंधी योजना का बजट 90% से भी ज्यादा कम किया

गांवों में बच्चे 10वीं से पहले छोड़ रहे स्कूल

इंदौर/ भोपाल | DBStar

FB MP Education News Group

प्रदेश के शहरी इलाकों में भले ही स्कूलों की चकाचौंध बनी हुई हो, लेकिन ग्रामीण इलाकों में हालात इसके उलट हैं। अनुसूचित जनजाति वर्ग के 42% बच्चे 10वीं में पहुंचने से पहले ही स्कूल से तौबा कर लेते हैं। सरकारी आंकड़ों में ही यह सच्चाई सामने आई है। बावजूद इसके सरकार ने इन बच्चों के स्कूल छोड़ने संबंधी योजना का बजट 90% से भी ज्यादा कम कर दिया। प्रदेश के 20 जिलों के 89 विकासखंडों में आदिवासी विकास विभाग द्वारा स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। इनमें कक्षा पहली से 5वीं के 31% से ज्यादा बालक और 27% से ज्यादा लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं। मिडिल स्कूल में यह आंकड़ा करीब 2 गुना हो जाता है। इसके अलावा केंद्र के अलावा राज्य सरकार ने भी छात्रवृत्ति का सालाना बजट आधा कर दिया है। 2019-20 में 11वीं-12वीं व कॉलेज के छात्रों की छात्रवृत्ति योजना में 30700 लाख रुपए का प्रावधान था। जिसे 2020-21 में घटाकर 17,250 लाख रुपए कर दिया गया।

लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा

एक्सपर्ट व्यू

आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित स्कूलों की जरूरत के अनुसार पाठ्य-सामग्री का न होना, प्रशासन की दुविधा के कारण उत्तरदायित्व हीनता का होना और बच्चों के लिए जरूरी गतिविधियों का समय पर न हो पाना इसकी खास वजह है।

डॉ. दामोदर, पूर्व सदस्य, एनसीईआरटी

15 साल में स्कूलों की बिल्डिंग बढ़ती गई, लेकिन शैक्षणिक गुणवत्ता पर ज्यादा फोकस नहीं किया गया। आदिवासी विकास विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के बीच तालमेल का अभाव होने से भी इस पर बहुत असर हुआ है।

रमाकांत पांडे, शैक्षणिक मामलों के जानकार

रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 17 मई

जेएलयू की प्रवेश परीक्षा 22 को, 25 मई को आएगा रिजल्ट

भोपाल| जागरण लेकसिटी यूनिवर्सिटी, मध्य भारत की सर्वाधिक पुरस्कार प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा प्रवेश परीक्षा जेएलयूईटी (जागरण लेकसिटी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट) 22 मई को आयोजित की जाएगी। 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं और यह अनिश्चित है कि कब परीक्षाओं का आयोजन होगा।इसलिए हायर एजुकेशन में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, जेएलयू ने प्रवेश परीक्षा का फिर से शुरू किया है और जेएलयूईटी के माध्यम से होगी। ऑनलाइन परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 17 मई है और परीक्षा के परिणाम 25 मई को घोषित किए जाएंगे। यह दो भागों में होगी, पहला भाग जेएलयूईटी के कुल अंकों में 60 % का योगदान देगा। वहीं, दूसरा भाग जेएलयूईटी के 40% का योगदान देगा। अंतिम स्कोर दोनों अंकों का योग होगा। जेएलयू के वाइस चांसलर डॉ. संदीप शास्त्री ने कहा कि जैसा कि कहा गया है कि सफलता उन लोगों को मिलती है, जो जल्दी शुरूआत करते हैं।

वैक्सीनेशन • 49 सेंटरों में 18 से अधिक उम्र के 5120 लोगों को लगाए गए टीके

18+ में बुकिंग वाले नहीं आए तो पहली बार वेटिंग वालों को बुलाया, ताकि बेकार न जाए वैक्सीन

राजधानी के 52 केंद्रों पर 45+कैटेगरी के 6976 लोगों को वैक्सीन लगाई

सिटी रिपोर्टर | भोपाल

राजधानी में बुधवार को 18+ वालों के लिए वैक्सीनेशन में हालात थोड़े बेहतर नजर आए। बुकिंग समस्या को छोड़कर सेंटर पर अच्छी तस्वीर देखने को मिली। डोज बेकार नहीं जाए, इसके लिए कर्मचारी बुकिंग वालों के नहीं आने पर वेटिंग वालों को कॉल करके बुला रहे थे। ताकि डोज बेकार नहीं जाए। 49 सेंटर पर 18+ वाले 5120 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। यानि तय मापदंड से 120 अधिक। जिन को कॉल करके सेंटर पर बुलाया, उनके लिए यह पल किसी सरप्राइज से कम नहीं था। वैक्सीन के लिए इंतजार कर रहे 45+ के लिए शहर व ग्रामीण इलाकों में 52 सेंटर बनाए गए थे। इस वर्ग के 6976 लोगों को वैक्सीन लगाई गई, इसमें में 5526 को सेकंड डोज लगाई गई। टीकाकरण के अफसरों ने औसतन 500 डोज का इंतजाम किया था। ऐसे शहर के करीब एक दर्जन सेंटर हैं। रात तक पोर्टल पर अपडेट जानकारी के अनुसार नेहरू नगर गर्ल्स हायर सेकंडरी स्कूल में 483, हायर सेकंडरी गर्ल्स स्कूल बैरागढ़ में 423, जीएमसी लाइब्रेरी में 484, कस्तूरबा अस्पताल में 467, गोविंदपुरा गर्ल्स हायर सेकंडरी स्कूल में 387, ओल्ड कैंपियन हायर सेकंडरी स्कूल में 456, आनंद नगर हायर सेकंडरी स्कूल में 314 लोगों को ही वैक्सीन लगाई गई।

टीकाकरण के लिए आज की व्यवस्था

11500 लोगों को लगेगी कोविशील्ड

5300 लोगों को लगेगी कोवैक्सीन

50 सेंटर रहेंगे 45+ कैटेगरी के लिए।

एक मिनट के भीतर ही फुल हो गई बुकिंग

बुधवार शाम 4.15 बजे के बाद बारी-बारी से स्लॉट ओपन किए गए। पहले 3-4 केंद्रों के लिए शेड्यूल बुकिंग शुरू हुई। लेकिन एक मिनट के भीतर ही बुकिंग फुल हो गई। शाम तक टीकाकरण देखने के बाद री-शेड्यूलिंग का निर्णय लिया जाता है। शाम 5 बजे स्टेट्स रिपोर्ट प्रशासन को भेजी जा रही है। वहां देखा जाता है कि कहीं ऐसे कोई केंद्र तो नहीं हैं, जो खाली जा रहे हों। संख्या कम हो तो नए केंद्रों की जानकारी अपलोड होती है।

सरकारी रणनीति... सेकंड डोज वालों को मिले प्राथमिकता

प्रदेश में 45 से अधिक उम्र वाले 50 लाख से ज्यादा लोगों को सेकंड डोज मिलने में दिक्कत आ रही है। स्लॉट तक बुक नहीं हो पा रहे हैं। बुधवार को सरकार की समीक्षा बैठक में यह बात सामने आई है। इसमें यह है कि 45 से अधिक उम्र वालों को शेड्यूल के हिसाब से पहली डोज लग रही है, जिससे सेकंड डोज वालों को वैक्सीन मिलने में दिक्कत हो रही है। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने नए सिरे से टीकाकरण नीति तैयार करने को कहा है क्योंकि जिन लोगों को को-वैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन की डोज लगी है, उन्हें दूसरी डोज 42 दिन बाद लगना जरूरी है। इधर, सरकार का दावा है कि 45+ के लोगों के लिए प्रदेश में 8 लाख वैक्सीन का स्टॉक है।

कोविड वैक्सीन

रजिस्ट्रेशन कराने के नाम पर 'एसएमएस वोर्म' से धोखाधड़ी

भोपाल| सायबर जालसाज अब वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के नाम पर गड़बड़ी कर रहे हैं। फर्जी एप्लीकेशन बनाकर उसकी लिंक मैसेज के जरिए भेजकर एप्लीकेशन डाउनलोड करने को कहते हैं। एप्लीकेशन के जरिए मैलवेयर (एक तरह का वायरस) फोन में आ जाते हैं और गोपनीय डेटा लीक होने की आशंका बढ़ जाती है। राज्य सायबर सेल को अब तक ऐसी शिकायतें तो नहीं मिली हैं, लेकिन नेशनल सायबर क्राइम के रिपोर्टिंग पोर्टल पर ये ट्रेंड जरूर देखने को मिला है। इसके बाद एडीजी राज्य सायबर योगेश चौधरी ने इस संबंध में एक एडवायजरी जारी की है। उन्होंने कहा कि यह एक तरह की फिशिंग तकनीक है जिसे 'एसएमएस वोर्म' नाम दिया गया है।

ऐसे बरतें एहतियात

- केवल Co-Win और आरोग्य सेतु एप के जरिए ही रजिस्ट्रेशन करें।
- एसएमएस से मिली लिंक क्लिक न करें।
- फर्जी कॉल, एसएमएस और ईमेल पर बिना पुष्टि के विश्वास न करें।
- ओटीपी, पिन, आधार नंबर, खाता नंबर आदि की जानकारी शेयर न करें।
- यदि आपके साथ ऐसा कोई अपराध हो तो उसकी शिकायत अपने नजदीकी पुलिस थाने में या www.cybercrime.gov.in या टॉल फ्री नंबर **155260** पर करें।

अब 30 मई तक भरे जाएंगे ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म

भोपाल | कोरोना का असर विश्वविद्यालयों के परीक्षा कार्यक्रम पर भी पड़ रहा है। उच्च शिक्षा विभाग ने कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए यूजी और पीजी कोर्स के ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 30 मई तक कर दी है। यह प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेज के छात्रों पर लागू होगी। गौरतलब है कि कोरोना की वजह से परीक्षाएं ओपन बुक पैटर्न से आयोजित होंगी। हाल में बीयू ने स्नातक स्तर की परीक्षओं के लिए 20 मई तक तारीख बढ़ाई थी। अब उच्च शिक्षा विभाग ने विवि के लिए परीक्षा फॉर्म बढ़ाने की तारीख 30 मई तक कर दी है। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक वर्तमान में अधिकांश जिलों में कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। इस वजह से बिना विलंब शुल्क के ही छात्र फॉर्म जमा कर सकेंगे।

आज का इतिहास

- **1643:** चिली में आए विनाशकारी भूकंप में सेंटियागो की एक तिहाई आबादी खत्म हुई।
- **1648:** दिल्ली में लाल किले का निर्माण पूरा हुआ।
- **1846:** अमेरिका-मैक्सिको के बीच टैक्सास पर तनाव, कांग्रेस ने पड़ोसी देश के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया।
- **1905:** भारत के पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद का जन्म।
- **1952:** स्वतंत्र भारत में संसद का पहला सत्र बुलाया गया।
- **1960:** मैक्स इसेलीन के नेतृत्व में स्विटजरलैंड का खोजी दल हिमालय में धौलागिरी पर्वत शिखर पर पहुंचा।
- **1962:** सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के दूसरे राष्ट्रपति बने।
- **1978:** देश का पहला ध्वजवाहक जहाज INS दिल्ली सेवामुक्त हुआ।

आज का इतिहास

1918 टी. बालासरस्वती - भरतनाट्यम की सुप्रसिद्ध नृत्यांगना का जन्म हुआ।

2001 आर. के. नारायण - अंग्रेजी में लिखने वाले उत्कृष्ट भारतीय लेखकों में से एक का निधन हुआ।

2011 बादल सरकार - प्रसिद्ध अभिनेता, नाटककार, निर्देशक और इन सबके अतिरिक्त रंगमंच के सिद्धांतकार का निधन हुआ।

1918 भारत ने राजस्थान के पोखरण में दो परमाणु परीक्षण किये।

1998 अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने परमाणु परीक्षण के विरोध में भारत के खिलाफ कड़े प्रतिबंध की घोषणा की।

2010 भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता इला भट्ट को 2010 के निवानो शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।